नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 043
दि. 15.11.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

डॉक्टरों की गिरफ्तारी से कांप उठा नूंह, तीन और धराए; इमाम भी हिरासत में, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में चीन-शिक्षित डॉक्टर का नाम उभरा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, हरियाणा का नूंह जिला सुरक्षा एजेंसियों के सर्वाधिक संवेदनशील रडार पर आ गया है। पिछले एक सप्ताह में यहां पाँच लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और इनमें तीन एमबीबीएस डॉक्टर, एक खाद विक्रेता और एक इमाम शामिल हैं। लगातार हो रही कार्रवाईयों ने पूरे क्षेत्र में तनाव और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जबकि मेडिकल छात्रों के अभिभावकों में भय और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। गुरुवार देर रात फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में की गई छापेमारी में दो और डॉक्टरों—सुनहेड़ा निवासी डॉ. मुस्तकीम और अहमदबास निवासी डॉ. मोहम्मद—को उठाया गया। दोनों अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे थे और इंटर्नशिप के अंतिम चरण में थे। डॉ. मुस्तकीम के बारे में सामने आया कि उन्होंने चीन से एमबीबीएस किया था और 2 नवंबर को ही अल-फलाह में अपनी इंटर्नशिप पूरी की थी। वहीं डॉ. मोहम्मद भी उसी यूनिवर्सिटी से जुड़कर इंटर्नशिप कर रहे थे। इन दोनों के संदिग्ध आतंकी उमर से संबंध होने की आशंका जताई गई है, जिससे उनका नाम जांच की रडार पर आया। बताया जाता है कि उमर की कार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल है।

इससे पहले नूंह से एक डॉक्टर और एक खाद विक्रेता भी हिरासत में लिए गए थे। खाद विक्रेता पर अमोनियम नाइट्रेट बेचने का शक है, जबकि तावडू के एक निजी अस्पताल में काम कर रहे डॉ. रिहान से भी लंबे समय तक पूछताछ की गई थी।

इन सभी का किसी न किसी रूप में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा होना पूरे मेवात क्षेत्र में चिंता का कारण बन गया है, जहाँ बड़ी संख्या में छात्र चिकित्सा शिक्षा लेने जाते हैं। सुनहेड़ा गांव में डॉ. मुस्तकीम के घर पर दो बार जांच टीमें पहुंच चुकी थीं। पहली बार अधिकारियों ने उनसे घंटों पूछताछ की थी, पर कार्रवाई नहीं की गई थी। गुरुवार को जब जांच दल दोबारा पहुँचा, तब उन्हें साथ ले जाया गया। परिवार का कहना है कि मुस्तकीम का व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है और वह किसी भी गलत गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। परिजन बताते हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे डॉ. उमर से वे कभी-कभार इलाज से संबंधित सलाह के लिए ही बात करते थे, लेकिन इससे अधिक किसी कनेक्शन की बात से वे इनकार करते हैं।

अहमदबास निवासी डॉ. मोहम्मद के परिवार पर गिरफ्तारी के बाद सन्नाटा पसरा है। उनका परिवार इलाके में शिक्षित और राजनीतिक प्रभाव वाला माना जाता है, लेकिन घटना के बाद घर के लोग मीडिया या स्थानीय लोगों से बात करने से बच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक हुई कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण बना दिया है।

जांच एजेंसियां इन दिनों नूंह में लगातार दबिश दे रही हैं। शुक्रवार को भी कई स्थानों पर पूछताछ और तलाशी ली गई। सूत्रों का कहना है कि यह जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि कई सुराग एजेंसियों को अभी खंगालने हैं। इसी बीच, खुफिया एजेंसियों से सामने आई जानकारी ने पूरे देश का ध्यान इस केस पर और गहरा कर दिया है। अब तक गिरफ्तार आठ संदिग्धों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वे 6 दिसंबर—बाबरी मस्जिद ढहाने की बरसी—के दिन दिल्ली समेत देशभर में कई जगह बड़े धमाके करने की योजना बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम भी कर लिया था और कई स्थानों की रेकी कर चुके थे। इस खुलासे के बाद जांच टीमों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 2019 से अब तक के रिकॉर्ड और फंडिंग की जानकारी मांगी है। वहीं कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले तीन दिनों में 500 से अधिक लोकेशन पर छापे मारते हुए 600 लोगों को हिरासत में लिया है।

दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें तीन की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में देश की शीर्ष जांच एजेंसियाँ हर संभावित संबंध और स्रोत की तह तक जाने में जुटी हुई हैं। नूंह में लगातार हो रही गिरफ्तारियों ने इस क्षेत्र को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में ला खड़ा किया है, जहाँ आने वाले दिनों में स्थिति और भी तेज़ी से बदल सकती है।

शेख़ हसीना के विरुद्ध ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला 17 नवंबर को, ढाका बना किले जैसा

(जीएनएस)। ढाका। बांग्लादेश की सत्ता से अपदस्थ हुईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो सबसे करीबी सहयोगियों के खिलाफ चल रहे बहुचर्चित मुकदमे का फैसला आखिरकार 17 नवंबर को सुनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को पूरी तरह खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में यह तारीख तय की, जहां सुरक्षा के इतने कड़े इंतज़ाम किए गए थे कि पूरा परिसर किसी सैन्य छावनी जैसा दिखाई दे रहा था। न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली पीठ ने अभियोजन और बचाव पक्ष की लंबी दलीलों को सुनने के बाद कहा कि अब फैसला सुनाने का समय आ गया है, और 17 नवंबर को इस मुकदमे का महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो जाएगा।

यह मुकदमा जुलाई 2023 के उस हिंसक विद्रोह से जुड़ा है, जिसने बांग्लादेश की राजनीति को हिला दिया था। उस समय देश भर में फैले उत्पात और जनविद्रोह के दौरान कथित रूप से मानवता-विरोधी अपराधों के होने का आरोप लगाया गया था। इन्हीं आरोपों के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को आरोपी बनाया गया। हालांकि मामून बाद में सरकारी गवाह बन गए, जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों पर पांच अलग-अलग मानवता-विरोधी अपराधों के आरोप दर्ज हैं, जो बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक इतिहास के सबसे संवेदनशील और विवादित प्रकरणों में से एक बन चुका है।

बुधवार सुबह से ही न्यायाधिकरण के आसपास का इलाका अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा बन गया था। सेना के जवान, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन बटालियन, सशस्त्र पुलिस बटालियन और पुलिस बल की भारी तैनाती ने पूरे क्षेत्र को एक उच्च-सुरक्षा क्षेत्र में बदल दिया था। कई बख्तरबंद वाहन और एंटी-रायट यूनिट की तैनाती ने संकेत दिया कि सरकार किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। अदालत तक जाने वाली सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी गई थी, जबकि कई स्थानों पर तलाशी चौकियां बनाई गईं। अवामी लीग द्वारा बुलाए गए बंद ने शहर का तनाव और बढ़ा दिया था। बंद के दौरान बम धमाकों और आगजनी की खबरों ने प्रशासन को और सतर्क कर दिया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ी। न्यायालय कक्ष के बाहर मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम पत्रकारों से बात करते हुए काफी दृढ़ दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि वह मानवता-विरोधी अपराधों को लेकर कठोर रुख अपनाएगी। ताजुल इस्लाम ने चेतावनी भी दी कि कोई भी व्यक्ति या समूह यदि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुकदमा केवल तीन व्यक्तियों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन सभी तत्वों के खिलाफ है जिन्होंने देश को हिंसा और अराजकता के गर्त में धकेला।

दूसरी ओर बचाव पक्ष ने यह दावा किया है कि फैसला आते ही शेख हसीना को बरी कर दिया जाएगा। बचाव पक्ष के वकील आमिर हुसैन ने आरोप लगाया कि चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून ने खुद को बचाने के लिए अपने पूर्व साथियों को फंसाकर सरकारी गवाह का सहारा लिया है।

दिल्ली में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, रिश्वत लेते आईटीडीसी के दो अधिकारी रंगेहाथों गिरफ्तार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सरकारी तंत्र के भीतर फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक और निर्णायक कार्रवाई की है। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईटीडीसी) के दो अधिकारियों—इंजीनियरिंग एवं वरिष्ठ प्रबंधक दिनेश महाजन और सहायक प्रबंधक सतीश कुमार—को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वे शिकायतकर्ता से सीधे रिश्वत की रकम स्वीकार कर रहे थे। सीबीआई की इस कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी विभागों में व्याप्त अनैतिक प्रथाओं और भ्रष्टाचार के जटिल तंत्र को उजागर कर दिया है, जहां सामान्य कार्यों के लिए भी कर्मचारियों को अवैध वसूली का सामना करना पड़ता है।

एजेंसी के अनुसार मामला तब शुरू हुआ जब शिकायतकर्ता ने सीबीआई से संपर्क कर बताया कि उसके लंबित बिलों पर मंजूरी देने में जानबूझकर देरी की जा रही है और सहायक प्रबंधक सतीश कुमार ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग की है। शिकायतकर्ता द्वारा पैसा देने से इनकार करने पर अधिकारियों ने उसे कई बार फोन कर राशि तय करने की कोशिश की। अंततः लंबी बातचीत और दबाव के बाद रकम घटाकर 40 हजार रुपये कर दी गई और पैसे किस प्रकार, कब और कहां देने हैं, इसकी पूरी योजना भी तैयार कर ली गई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने इसे 12 नवंबर को औपचारिक रूप से दर्ज किया और उसके तुरंत बाद एक विस्तृत ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी।

शिकायतकर्ता की ओर से तय समय पर जैसे ही रिश्वत की रकम सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई, सीबीआई की टीम पहले से मौजूद थी और उसने दोनों अधिकारियों को वहीं पर रंगेहाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी की यह घटना इतनी अचानक और सटीक थी कि आरोपी दो मिनट तक समझ ही नहीं पाए कि उनके चारों ओर सीबीआई की टीम कब और कैसे पहुंच गई। सीबीआई ने मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली और दोनों अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रारंभिक जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर माना जा रहा है कि इस मामले के तार आईटीडीसी के भीतर कई और कर्मचारियों तक जुड़ सकते हैं, क्योंकि भुगतानों में देरी और अवैध वसूली की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। इस कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के बीच भी खलबली मच गई है, क्योंकि आईटीडीसी जैसे प्रतिष्ठित उपक्रम में इस तरह की रिश्वतखोरी ने न केवल उसकी साख पर सवाल उठाया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि भ्रष्टाचार किस हद तक जड़ें जमा चुका है।

राहुल गांधी का बड़ा बयान: "शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था बिहार का चुनाव", नतीजों के बाद उठाए सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक हलचल को एक नई दिशा दे दी है और इन्हीं नतीजों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहली और बेहद स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक लंबा संदेश साझा करते हुए कहा कि बिहार का चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था और जो परिणाम सामने आए हैं, वे जितने अप्रत्याशित हैं, उतने ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर गहरे सवाल भी खड़े करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि वे बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों और तमाम तरह की शंकाओं के बावजूद महागठबंधन पर भरोसा जताया और लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है और जनता के बीच जो माहौल दिखाई दे रहा था, वह अंतिम नतीजों में परिलक्षित नहीं हुआ। उनके अनुसार यह चुनाव एक ऐसी परिस्थितियों में संपन्न हुआ, जहां बराबरी की लड़ाई संभव ही नहीं थी, चुनावी माहौल में निष्पक्षता का संतुलन शुरू से ही डगमगाया हुआ था और सत्ता पक्ष के पक्ष में तमाम कारक साफ तौर पर दिखाई देते रहे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह लड़ाई

अब किसी एक चुनाव या सत्ता परिवर्तन की नहीं रह गई, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और भारत के भविष्य की रक्षा की लड़ाई बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि परिणाम भले ही एनडीए के पक्ष में आए हों, लेकिन इससे उस सामाजिक–राजनीतिक विमर्श को कमजोर नहीं किया जा सकता, जिसे INDIA गठबंधन ने चुनाव में उठाया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों और जनता के वास्तविक मुद्दों को खारिज नहीं माना जा सकता क्योंकि वे बिहार की भावनाओं और जमीनी सच्चाई से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और INDIA गठबंधन इस परिणाम की व्यापक समीक्षा करेंगे, हर पहलू का विश्लेषण किया जाएगा—मतदान के प्रारूप से लेकर मतगणना की प्रक्रियाओं तक, जनभावनाओं के तिरछे रूपांतर से लेकर चुनावी मशीनरी के व्यवहार तक। राहुल गांधी ने कहा कि यह समीक्षा केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि आने वाली राजनीतिक रणनीति को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कदम होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि विपक्ष लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी, संगठित और तेज करेगा ताकि आने वाले समय में देश के नागरिकों को और अधिक जवाबदेह और जवाबदेही स्वीकार करने वाली राजनीतिक व्यवस्था मिल सके। राहुल गांधी की यह टिप्पणी उस समय सामने आई है जब बिहार में एनडीए ने भारी जीत हासिल की और महागठबंधन को बेहद निराशाजनक परिणाम झेलने पड़े। राजनीतिक विश्लेषक अब राहुल गांधी के इस बयान को आने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतने सीधे शब्दों में किसी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। उनके इस वक्तव्य ने राजनीतिक बहस को फिर से गरमा दिया है और आने वाले दिनों में यह बयान दिल्ली से पटना तक राजनीतिक बयानबाज़ी और आरोप–प्रत्यारोप का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

बिहार में नीतीश की प्रचंड वापसी, एनडीए ने 203 सीटों पर झंडा गाड़कर रचा नया इतिहास

(जीएनएस)। पटना। बिहार की राजनीति में इस बार जो तस्वीर उभरी है, उसने दशकों पुराने सभी समीकरणों को हिला दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही यह साफ हो गया कि राज्य की जनता ने एकतरफा समर्थन एनडीए को देकर एक बार फिर नीतीश कुमार पर भारी भरोसा जताया है। बिहार की 243 सीटों में से लगभग 203 सीटों पर कब्जा जमाकर एनडीए ने न सिर्फ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जनता के मन में स्थिरता और अनुभव का मूल्य अभी भी सबसे ऊपर है। इस प्रचंड जीत ने नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त कर दिया है और इससे उनकी राजनीतिक यात्रा में एक नया स्वर्ण अध्याय जुड़ गया है।

पटना के राजनीतिक गलियारों से लेकर ग्रामीण चौपालों तक, इस चुनाव को लेकर एक विशेष किस्म की हलचल थी। पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे—गठबंधन बदलना, सत्ता परिवर्तन, जनसुराज का उभार, और महागठबंधन का बढ़ता आत्मविश्वास। लेकिन मतदान के बाद जिस तरह का परिणाम सामने आया, उसने हर उस दावे को धराशायी कर दिया, जो महागठबंधन की तरफ से लगातार किए जा रहे थे। तेजस्वी यादव को विपक्ष ने अपना सर्वाधिक चमकदार चेहरा बताकर जनता के सामने पेश किया था, लेकिन मतदाताओं ने यह फैसला दे दिया कि अनुभव और स्थिरता को बदलने वाली राजनीति अभी बिहार में स्वीकार्य नहीं।

राज्य की चुनावी हवा में शुरू से ही कई तरह की चर्चाएँ थीं—महागठबंधन के बड़े दावे, जनसुराज पार्टी का बढ़ता ग्राउंड नेटवर्क, भाजपा की मजबूत चुनावी मशीनरी और नीतीश कुमार का व्यापक प्रशासनिक

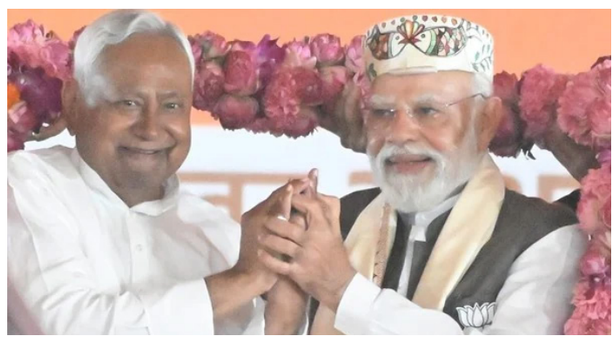

अनुभव। लेकिन जब परिणाम आए तो चुनाव आयोग के दफ्तर से लेकर गांवों तक सिर्फ एक ही बात थी—"बिहार ने इस बार बड़े अंतर से फैसला सुनाया है।" एनडीए की 203 सीटों की बढ़त ने राजनीति में ऐसा अंतर पैदा कर दिया जैसा पिछले पंद्रह-सोलह वर्षों में भी देखने को नहीं मिला था।

विपक्ष की हालत इस चुनाव में बदतर हो गई। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद, जिसने पिछले चुनाव में 75 सीटें जीती थीं, इस बार महज 25 सीटों पर सिमट गई। यह अंतर इतना बड़ा था कि पार्टी कार्यालय में गहरी खामोशी छाई रही। कई वरिष्ठ नेताओं ने माना कि जनता उनसे नाराज़ नहीं थी, बल्कि भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं थी। कांग्रेस की स्थिति तो और भी कमज़ोर रही—19 से घटकर सिर्फ 6 सीटों पर आ पहुँची। यह परिणाम उस चुनावी विमर्श को भी झटका देता है जिसमें कहा जा रहा था कि बिहार में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सत्ता विरोधी लहर पैदा हुई है।

दूसरी तरफ, जनसुराज पार्टी की कहानी इस चुनाव की सबसे दिलचस्प लेकिन सबसे निराशाजनक कहानी बनकर सामने आई। प्रशांत किशोर ने लंबे 'जन-संवाद' और पैदल यात्राओं से जिस जनाधार का दावा किया था, वह मतपेटियों में अनुवादित नहीं हुआ। 200 से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतारने के बावजूद पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, बल्कि उसे मिलने वाला वोट प्रतिशत भी बहुत कम रहा। यह दृश्य यह बताता है कि बिहार की राजनीति में सामाजिक नेटवर्क और जमीन पर काम करने का महत्व तो है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उससे कहीं अधिक स्थायी संगठन की जरूरत होती है।

उधर एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में एक बार फिर अपनी पकड़ का सबूत दिया। ओवैसी की पार्टी ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की, जो 2020 की पुनरावृत्ति जैसा था। इससे संकेत मिलता है कि सीमांचल की राजनीति में एआईएमआईएम अब एक स्थायी खिलाड़ी बन चुकी है। जैसे-जैसे रात बढ़ती गई और परिणाम स्थिर हुए, एनडीए के दफ्तरों में उत्साह का माहौल गहराता गया। भाजपा इस चुनाव में अपने इतिहास का सबसे मजबूत प्रदर्शन करती दिखी, जबकि जदयू ने भी कई चुनावी सर्वेक्षणों को गलत साबित करते हुए जबरदस्त वापसी की। नीतीश कुमार ने चुनावी रैलियों से लेकर संगठन की बैठकों तक, हर बार यही कहा था कि वह अपनी विकास योजनाओं और सुशासन के मॉडल पर जनता का भरोसा जीतेंगे। परिणामों ने दिखा दिया कि जनता ने उनके इस दावे पर विश्वास किया है। गांवों में मतदाताओं की बातचीत से भी इस बार के चुनाव की भावना समझी जा सकती है। कई जगह लोगों ने यह कहा कि "जांच-पड़ताल के वक्त नीतीश को आज़माया जा चुका है, अब किसी नए चेहरे पर दांव लगाकर जोखिम क्यों लिया जाए।" खासकर महिलाओं में यह भावना बहुत प्रबल रही कि बिहार में कानून-व्यवस्था और योजनाओं का लाभ समय पर मिला है। शराबबंदी और महिला समूहों की सक्रियता ने भी एनडीए को बड़े पैमाने पर समर्थन दिलाया।

शहरों में युवा मतदाताओं की राय भी दिलचस्प रही। बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे के बावजूद युवाओं ने विपक्ष की जगह एनडीए को वोट देने का कारण बताते हुए कहा कि "जो मॉडल दिख रहा है, वही आगे बढ़ेगा।" विपक्ष के पास कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं था — यह बात भी युवा मतदाताओं के मन में गूंजती रही।

इन सभी पहलुओं को मिलाकर यह चुनाव बिहार के इतिहास में एक ऐसी मिसाल बन गया है, जिसमें जनता ने स्थिरता, अनुभव और विश्वसनीयता को सबसे ऊपर रखा और इसे अभूतपूर्व बहुमत के रूप में एनडीए को सौंप दिया। नीतीश कुमार के सामने अब बड़ी चुनौती यह होगी कि वे इस ऐतिहासिक जनादेश को ऐसे विकास में बदलें जो लोगों की उम्मीदों के अनुरूप हो। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और प्रशासन का स्वरूप किस दिशा में जाएगा, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तय है—इस चुनाव ने बिहार की राजनीतिक धारा को कई वर्षों के लिए बदलकर रख दिया है।

संपादकीय

मगर घरेलू बजट पर अभी भी दबाव

सरकारी आंकड़े हमेशा सार्वजनिक विमर्श में रहते हैं। राहत और तरक्की के दावे विभिन्न सरकारों के दौर में अकसर सामने आते हैं। टकसाली सत्य यही है कि राहत व तरक्की का जमीनी प्रभाव भी नजर आना चाहिए। मसलन, जिस जनहित की बात की जा रही है, उसका अहसास भी आमजन को होना चाहिए। प्रथम दृष्टया यह राहतकारी माना जाना चाहिए कि देश में खुदरा महंगाई की दर में गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि अक्तूबर में देश की मुद्रास्फीति की दर घटकर 0.25 रह गई है। यह स्थिति साल 2013 के बाद से सबसे कम बताई जा रही है। जाहिर है सरकार ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि माना है। सरकार का दावा है कि मुद्रास्फीति में यह बड़ी गिरावट कीमतों पर मजबूत नियंत्रण और कुशल वित्तीय प्रबंधन को ही दर्शाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम परिवारों के लिये इस राहत का अहसास करना इतना भी आसान नहीं है। दरअसल, मुद्रास्फीति में इस गिरावट में मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कम कीमतों की भूमिका देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में की गई जीएसटी दरों में कटौती का प्रभाव भी बताया जा रहा है। जिसके चलते उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर मुद्रास्फीति में यह तीव्र गिरावट पिछले साल की ऊंची कीमतों के आधार प्रभाव को भी दर्शाती है, जो शायद लंबे समय तक न रहे। प्रथम दृष्टया भले ही यह प्रभावशाली लगे, लेकिन कई लोग अभी भी उच्च घरेलू खर्चों का दबाव महसूस कर रहे हैं। दूध, दालों और सब्जियों जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में अभी भी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। जिससे लोगों का पारिवारिक बजट प्रभावित हो रहा है। इसलिए, जहां समग्र मुद्रास्फीति दर में गिरावट आई है, वहीं आम लोगों के लिये व्यावहारिक जीवन यापन की लागत में उसी तरह की गिरावट महसूस नहीं की जा रही है। वैसे देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के लिये यह स्थिति राहत और चुनौती दोनों ही लेकर आ रही है। दरअसल, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुख्य मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं हैं, ऊंची बनी हुई है। जो यह भी दर्शाती है कि मूल्य दबाव पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। ऐसे में फुटकर मुद्रास्फीति इतनी कम होने के कारण उद्योग जगत की तरफ से दलील दी जा सकती है कि भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर की अपनी बैठक में उधार लेने और खर्च को प्रोत्साहित करने के लिये बैंक ब्याज दरों में कटौती पर विचार करे। लेकिन केंद्रीय बैंक को इस दिशा में सावधान भी रहना होगा। यदि केंद्रीय बैंक इस दिशा में कोई कदम उठाता है तो मुद्रास्फीति फिर से बढ़ भी सकती है। खासकर, अगर वैश्विक तेल की कीमतों में कोई अप्रत्याशित उछाल आ जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में रुपया कुछ कमजोर होता है। वैसे देखा जाए तो इस दौरान, मुद्रास्फीति में गिरावट का बेहतर ढंग से उपयोग मांग बढ़ाने, आय बढ़ाने और खाद्य कीमतों को स्थिर बनाने में भी किया जा सकता है। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी देश में मुद्रास्फीति की कम दर एक छोटी अवधि में विकास को पुनर्जीवित करने में मदद भी कर सकती है। लेकिन इसकी शर्त यही है कि लापरवाही से सरकारी खर्च न बढ़ाया जाए या कोई खराब योजना का क्रियान्वयन न हो। ऐसे में आंकड़े तो दिखा सकते हैं कि कीमतें नियंत्रण में हैं, लेकिन लोगों के अनुभव कुछ और ही कहानी बयां कर सकते हैं। देश में सच्ची प्रगति तभी मानी जा सकती है, जब राहत हर घर तक पहुंचेगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि राहत सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही नजर न आए। यह भी हकीकत है कि कीमतों का संतुलन मांग व आपूर्ति के संतुलन पर निर्भर करता है। जिसकी ओर भी सत्ताधीशों को ध्यान देने की जरूरत होती है। निस्संदेह, ऐसे में खुदरा महंगाई में गिरावट सुखद ही है, लेकिन जरूरत इस बात की भी कि यह राहत आम आदमी को भी महसूस होनी चाहिए।

चुनावी 'पर्यटन' पर लगाम लगाने का समय

"देशकेजनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, आपको केवल वहीं बतौर मतदाता पंजीकरण का अधिकार है जहां के आप 'सामान्य रूप से निवासी' हैं व वहीं रहने का इरादा रखते हैं। यह मूल्यांकन तथ्य आधारित है। नियमानुसार, यदि कोई व्यक्ति आजीविका के लिए अस्थाई तौर पर स्थानांतरित हो तो उसका वोट सूची से नहीं हटना चाहिये।"

आरोप सामने आए हैं कि दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों से बिहार में हज़ारों मतदाता पंजीकरण कराने और वोट डालने आए। इसका व्यापक रूप से मशहूर हुआ उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर का है, जिन्होंने कथित तौर पर दिल्ली की मतदाता सूची से अपना नाम हटवाया और बिहार में मतदान करने के लिए वहां अपना नाम दर्ज करा लिया। अगर आरोप सही हैं, तो यह रिवायत गैरकानूनी है।

भारत का चुनावी कानून इस बारे में स्पष्ट व सरल रेखा खींचता है : आप केवल वहीं पंजीकरण करा सकते हैं जहां आप 'सामान्य रूप से निवासी' हैं। घर का मालिक होना, अपने पैतृक गांव की यादें ताज़ा करना या चुनाव से पहले कुछ समय वहां रुकना, आपकी योग्यता नहीं बनता। सामान्य निवास का मतलब है, आप वास्तव में कहां रहते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 के तहत, कोई व्यक्ति केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन कराने का हकदार है जहां वह 'सामान्य रूप से निवासी' है। धारा 17 और 18 दो गैर-समझौताकारी शर्तें जोड़ती हैं : आप एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं हो सकते, और आप एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं हो सकते। धारा 20 स्पष्ट करती है कि 'सामान्यतः निवासी' का क्या अर्थ है और, महत्वपूर्ण यह, कि स्पष्ट करती है कि केवल संपत्ति का स्वामित्व होने पर सामान्य निवास का दावा नहीं बन जाता।

सामान्य निवास एक तथ्य-आधारित, निरंतर रहने का साक्षात परीक्षण है - जहां आप आदतन रहते हैं और रहने का इरादा रखते हैं; अस्थायी अनुपस्थिति इसे विराम नहीं देती। अंत में, धारा 31 वोटर सूची से नाम हटाने के संबंध में झूठे विवरण (मसलन, नया वोटर पंजीकरण दाखिल करते समय

मौजूदा नामांकन छिपाना) को आपराधिक जुर्म बनाती है, जिसके तहत एक वर्ष तक कारावास, या जुर्माना, या दोनों दंड का प्रावधान है। हालांकि संहिता में 'छह माह के नियम' का उल्लेख नहीं, परीक्षण सामान्य निवास से किया जाता है, जिसका मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर किया जाता है —न कि यहां-वहां की तारीखों के हिसाब से । दूसरा, काम या यात्रा के वास्ते अस्थाई अनुपस्थिति आपके सामान्य पते पर बनी वोट से वंचित नहीं करती; आप इसे इसलिए नहीं खोते कि आप कुछ हफ़्तों के लिए बाहर थे, और न ही इसलिए पा सकते हैं कि आप मतदान से ऐन पहले पहुंचे थे। भारत के चुनाव आयोग ने हमेशा से 'सामान्य रूप से निवासी' की व्याख्या छह महीने अवधि को आधार बनाकर की। यह निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिचालन प्रारूप में दिखाई देता है, जब वे नाम हटाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं।

ईआरओ संहिता पुस्तक में ऐसे मामलों के लिए बाकायदा एक मॉडल नोटिस शामिल है, जब कोई व्यक्ति स्थानांतरित हुआ प्रतीत होता होः 'चूंकि, अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया है कि आप पिछले छह माह से अधिक से वोटर सूची में दिए गए अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित पाए गए हैं। इसलिए, माना जाता है कि आप निर्वाचन क्षेत्र में उपर्युक्त पते पर सामान्य रूप से निवासी नहीं रहे'।

यदि मतदाता बसों से लाए गये, कमजोर दावों पर वोटर लिस्ट में शामिल कर लिए और भविष्य में फिर अपनी वोट दिल्ली या हरियाणा में स्थानांतरित करने का इरादा रखते हैं, तो यह प्रवास नहीं; गलत प्रतिनिधित्व है। यह निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के मूल उद्देश्य को विफल कर देता है, जिसका उद्देश्य उन लोगों की जनादेश को प्रतिबिंबित करना है जो सामान्यतः वहां के समाज में रहते हैं - वहां के स्कूल, अस्पताल, जलापूर्ति, सड़कों और पुलिस व्यवस्था का प्रयोग करते हैं - और जो स्थानीय शासन के फैसले भुगतते हैं।

इसका हल श्रमिकों और छात्रों के लिए वोट नामांकन कठिन बनाना नहीं। इसका उद्देश्य असल विस्थापित लोगों को पैंतरेबाज विस्थापितों से अलग करना है, और जहां धोखाधड़ी स्पष्ट हो, वहां दृढ़ कदम उठाना है। इसके पांच व्यावहारिक चरण हैं:

पहला, कानून पहले से ही किसी व्यक्ति के सामान्य निवासी न रहने पर पूछताछ करने और नाम हटाने की अनुमति देता है - एक नोटिस जारी करने और सुनवाई के बाद। उपरांत, बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) पड़ोसियों के बयान दर्ज करे, रिहायश की पुष्टि करे और हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करे; ईआरओ को हर मामले पर अपने दिमाग से विचार करना चाहिए।

दूसरा, अतंर राज्यीय डुप्लीकेशन : ईआरओ-नेट को ऐसे कॉन्फिगर करना कि व्यक्ति द्वारा हाल में किसी अन्य राज्य में दाखिल नामांकन फॉर्म 6 आवेदन को खुद-ब-खुद चिह्नित कर परखा जा सके; ऐसे मामले स्वीकार करने से पहले मजबूत प्रमाण (हालिया किराया समझौता, रोजगार/शिक्षा प्रमाण पत्र, उपयोगिता बिल) लिए जाएं। जहां शक अधिक हो,वहां यह कोई बाधा न होकर भरोसा कायम रखने का एक कदम है। तीसरे, आपराधिक निवारक का प्रयोग करें - कभी कभार, लेकिन स्पष्टतया। जानबूझकर गलत घोषणा ('मैं कहीं और नामांकित नहीं') के साथ फॉर्म 6 भरना अधिनियम की धारा 31 के तहत अपराध है। चुनिंदा अभियोजन हज़ार चेतावनियों से ज्यादा प्रभावी होंगे। इसका उद्देश्य सामूहिक दंड नहीं;यह जानबूझकर की गई गलतबयानी के स्पष्ट परिणाम है।

चौथा, चुनाव बाद ऑडिट किया जाए। मतदान के तीन माह बाद संवेदनशील क्षेत्रों में 'नए वोटर्स' का यहां-वहां से नमूना उठाया जाए। यदि कोई पैटर्न दिखे- कई वोटर दिए पते पर मौजूद नहीं व कभी थे भी नहीं - तो वह कार्रवाई योग्य सबूत है, अफवाह नहीं। पांचवां, असल विस्थापित मतदाता की सुरक्षा करें। लचीला दस्तावेज़ीकरण विकल्प दिया जाए (स्व-प्रमाणित निवास प्रमाणपत्र, नियोक्ता अथवा संस्थान से जारी प्रमाण पत्र) को बीएलओ सत्यापन के साथ रखें, ताकि गरीब, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले और एक जगह पर न रहने वाले नागरिक वंचित न रहें।

उस बहुचर्चित प्रोफेसर का क्या? अगर वह असल में दिल्ली के सामान्य निवासी नहीं रहे, बिहार चले गए हैं और वहीं रह रहे हैं, तो बिहार में उनका पंजीकरण वैध होगा (दिल्ली का पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए)। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया- केवल दिल्ली में अस्थाई नाम कटवाया और बिहार में मतदान खातिर नामांकन करवाया और फिर दिल्ली में मतदाता रूप में बहाल होने का इरादा है - तो यह मामला जांच, नाम हटाने और अभियोजन का आदर्श मामला है। यहां बात किसी एक मामले को सनसनीखेज बनाने की नहीं, बल्कि मामला-दर-मामला, तार्किक आदेशों के जरिये स्पष्ट सिद्धांत की रक्षा करना है। मैं अक्सर कहता हूं कि मतदाता सूची हमारे लोकतंत्र की सबसे कमजोर कड़ी है। इसकी सुरक्षा मतदाता को ही साफ करके नहीं बल्कि सूची में संशोधन कर संरक्षित करने में है। अगर बिहार से जुड़े आरोप सही हैं, तो उनकी जांच हो- नोटिस, सुनवाई और मुंह बोलते आदेशों के साथ। जहां कहीं गलतबयानी साबित हो, नाम हटाएं और मुकदमा चलाएं। इसी वक्त, असल घरेलू प्रवासियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए;वे नागरिक हैं, कोई संदिग्ध नहीं।

प्रेरणा

जब बुद्धि ने गोलियों से भी तेज़ दौड़ लगाई

अंग्रेजों का शासन उस समय अपने सबसे क्रूर रूप में था। भारत का हर कोना, हर मार्ग और हर गली में अंग्रेज सिपाही गश्त करते नजर आते थे। स्वतंत्रता की आग पूरे देश में भड़क रही थी और इस आग को तेज़ करने वालों में सबसे चमकता हुआ नाम था—चंद्रशेखर आज़ाद। उनके साहस, उनकी वीरता और ब्रिटिश सरकार को छकाने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें एक जिंदा किंवदंती बना दिया था। लेकिन जितने बड़े क्रांतिकारी आज़ाद थे, उतनी ही बड़ी उनके खिलाफ अंग्रेज सरकार की नफरत। वे हर पल उनका पीछा कर रहे थे।

ऐसा ही एक दिन था जब आज़ाद किसी गुप्त मिशन से लौट रहे थे। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि दो-तीन संदिग्ध चेहरे लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। ऐसे हालात में उनका दिमाग सामान्य आदमी की तुलना में कई गुना तेज़ काम करता था। वे तेजी से गलियों में मुड़े, भीड़ में घुले, और एक पुरानी कोठी के पीछे बने तंग रास्ते से निकलते हुए अपने एक विश्वसनीय साथी के घर पहुंचे।

यह घर आज़ाद के लिए हमेशा सुरक्षित साबित हुआ था। उसके मालिक, उसकी पत्नी और परिवार के लोग आज़ाद को केवल एक क्रांतिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह देखते थे। आज़ाद घर में घुसते ही थककर चुपचाप एक कोने में बैठ गए, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि खतरा उनके पीछे-पीछे उसी घर तक पहुंच चुका था।

कुछ ही मिनटों में बाहर घोड़ों की टापें सुनाई दीं। अंग्रेज पुलिस का एक बड़ा दस्ता घर के बाहर आ खड़ा हुआ। उनके भारी जूते, कमर पर लटके हथियार और कठोर आदेशों की आवाज़ माहौल को डर से काँपने लगा। दरवाज़ा ठोका गया नहीं, बल्कि जैसे धक्का देकर हिलाया गया।

घर का मालिक पूरी शांति से बाहर आया, लेकिन उसकी आँखों में चिंता की छाया साफ दिखाई देती थी।

इंस्पेक्टर ने कठोर स्वर में कहा—

"हमें सूचना मिली है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद इस घर में छिपे हैं। हम तलाशी लेंगे।"

घर का मालिक ठहरे हुए स्वर में बोला—

"मेरे घर में कोई आज़ाद नहीं हैं, आप गलतफहमी के शिकार हैं।"

पर अंग्रेज पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। उनके सैनिक घर की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि घर की मालकिन—एक तेज़, साहसी और असाधारण समझ वाली महिला—अचानक आगे आई।

उसने स्थिति की गंभीरता को पलभर में समझ लिया। एक ओर भीतर छिपे आज़ाद की साँसें, दूसरी ओर बाहर मौत की परछाई। यदि उसने अब एक क्षण भी गंवाया, तो पूरा घर बर्बाद हो सकता था। लेकिन वह डरी नहीं। बल्कि उसके दिमाग में एक ऐसा विचार कौंधा, जिसका अंदाज़ा आज़ाद जैसी तेज बुद्धि वाले क्रांतिकारी ने भी नहीं लगाया था।

उस दिन मकर संक्रांति थी। इस तथ्य ने मानो उसे पूरे संकट से निकालने की चाबी दे दी। उसने इतनी ऊँची आवाज़ लगाई कि पुलिसवालों के कान सन्न हो गए। वह सीधे अंदर की ओर देखकर ऐसे चिल्लाई जैसे किसी नौकर को डांट रही हो—

"अरे ओ नासमझ! कितना खेलेगा बच्चों के साथ? त्योहार का दिन है और मिठाई की टोकरी तैयार खड़ी है। उठ इसे और मेरे पीछे-पीछे चल। पूरे मोहल्ले में मिठाई बाँटनी है!"

उसकी आवाज़ इतनी प्राकृतिक, इतनी घरेलू और इतनी भरोसेमंद थी कि किसी को भी संदेह नहीं हो सकता था कि यह अभिनय है।

भीतर बैठे चंद्रशेखर आज़ाद ने इस आवाज़ को सुना और सिर्फ एक क्षण लगा उन्हें समझने में कि यह उनकी जान बचाने का रास्ता है। वे तुरंत चुपचाप मिठाइयों से भरी बड़ी टोकरी सिर पर रखकर बाहर आए और बिल्कुल सामान्य भाव से उस महिला के पीछे-पीछे चल पड़े।

पुलिसवालों ने उन्हें देखा जरूर, लेकिन उनके दिमाग में यह खयाल भी नहीं आया कि जिस युवक को वे एक साधारण घरेलू नौकर समझ रहे हैं, वही व्यक्ति वह है जिसे वे महीनों से ढूंढ रहे हैं—हज़ारों सैनिकों के बावजूद जो उनके हाथ नहीं आ पा रहा था।

महिला पूछताछ में उलझे पुलिसवालों के सामने से ऐसे गुजर गई मानों वह घर की रोज़मर्रा की गतिविधियों का हिस्सा हो। उसकी चाल में धड़कन भी नहीं बदलती थी। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न ही कोई जल्दबाज़ी। आज़ाद उसके पीछे उतनी ही शांति से चल रहे थे जितनी शांति से कोई मजदूर त्योहार पर काम पर निकल पड़ता है। घर से दो गलियाँ दूर जाकर महिला के कदम धीरे हुए। उसने मुड़कर आज़ाद की ओर देखा। उसकी आँखों में गर्व और साहस की चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा—

"अब आप यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। ईश्वर आपकी रक्षा करे।"

आज़ाद ने उसे प्रणाम की मुद्रा में देखा, फिर बिना समय गंवाए आगे बढ़ गए। उनकी चाल में वही दृढ़ता थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्हें मौत सामने दिख जाए, पर वे उससे आँखें चुराकर जीवन की ओर भाग निकलें।

उस दिन न कोई मिठाई बाँटी गई, न कोई त्योहार मनाया गया। लेकिन एक महिला की बुद्धिमानी, उसके साहस और उसकी अद्भुत तत्परता ने भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक की जान बचा ली।

इतिहास में कई युद्ध तलवारों से जीते जाते हैं, कई गोलियों से। पर यह युद्ध—एक महिला की बुद्धि, धैर्य और निर्णायक चतुराई ने जीता। यह बताता है कि संकट के क्षणों में अक्सर वही लोग सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिनके हाथों में न हथियार होते हैं, न कोई शक्ति—सिवाय उनकी अद्भुत सूझबूझ के।

भूटान की पॉवर ग्रिड में भारतीय निजी क्षेत्र की बढ़त

भूटान गए पीएम मोदी को बोलना ही पड़ा कि दरियागंज लालबत्ती विस्फोट में शामिल दहशतगर्दों को हम बख्शेंगे नहीं। भूटान 4 से 17 नवंबर, 2025 तक 'वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव' की मेजबानी कर रहा है। इसमें दुनियाभर के बौद्ध नेता, शांति समर्थकों की शिरकत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक पंथ दो नहीं, तीन काज के वास्ते थिम्पू गए थे। पहला, थिम्पू में चल रहे वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भागीदारी। दूसरा, भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक की 70वीं जयंती पर शुभकामना देना। और तीसरा, 1020 मेगावाट पुनात्सांगछू-II जल-विद्युत परियोजना का उद्घाटन।

हिमालय के ग्लेशियरों से निकली फोछू और मोछू नदियों की धारा से निर्मित पुनात्सांगछू नदी, दक्षिण की ओर बहकर पश्चिम बंगाल के मैदानों में प्रवेश करती है, और अंततः ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अगस्त, 2025 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना की दो इकाइयों को चालू कर दिया था। लेकिन, इसका उद्घाटन कार्यक्रम बाक़ी था। पीएम मोदी ने कहा कि इससे भूटान के जलविद्युत उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी, और भारत को इससे बिजली का निर्यात होगा।

पश्चिमी भूटान के वांगडू फोडरंग जिले के पुनात्सांगछू जलविद्युत परियोजना के लिए जुलाई, 2006 में समझौता हुआ था। यह परियोजना दो चरणों में विकसित की गई। यह दिलचस्प है, कि पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना अभी पूरी नहीं हुई। भूवैज्ञानिक समस्याओं के कारण इसमें काफी देरी हुई है। इस परियोजना को 2013 और 2019 में ढलानों में आई खराबी के कारण भारी नुकसान हुआ था। 31 मार्च, 2025 को पुनात्सांगछू-I हाइड्रो प्रोजेक्ट का अपडेट था, कि इसका 87.75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन इसके चालू होने की कोई निश्चित तिथि तय नहीं है।

पीएम मोदी की इस यात्रा में भारत और भूटान ने 7 समझौते किए, जिसमें 4000 करोड़ रुपये का ऊर्जा ऋण, 1020 मेगावाट की पनबिजली परियोजना का उद्घाटन और 89 किमी लंबी दो नई रेल लिंक परियोजनाओं की मंजूरी शामिल है। 4000 करोड़ रुपये का ऊर्जा ऋण क्या भावी परियोजनाओं पर खर्च होंगे? भूटान स्वच्छ ऊर्जा के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जिसमें अडानी, रिलायंस और टाटा ने बड़े पैमाने पर जलविद्युत और सौर परियोजनाएं विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

भूटान, वर्ष 2030 के दशक की शुरुआत तक 1.9 गीगावाट से अधिक बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। उसकी ऊर्जा महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत के तीन प्राइवेट प्लेयर्स ने लीड लेनी शुरू की है। अडानी का 570 मेगावाट का वांगछू प्रोजेक्ट, टाटा का 600 मेगावाट का खोलोंगछू और रिलायंस का 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा फार्म शामिल है। सितंबर, 2025 में, ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन (डीजीपीसी) और अडानी पावर ने 570 मेगावाट वांगछू जलविद्युत परियोजना के लिए शेयरधारक समझौते और रियायत पर हस्ताक्षर किए। यह उनकी व्यापक 5 गीगावाट साझेदारी के तहत पहली बड़ी परियोजना है। वांगछू प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, जिसकी विकास अवधि पांच वर्ष होगी, जिससे लगभग 2031 तक पहली बिजली इकाई उत्पादन कर सकेगी। यह परियोजना नए द्विपक्षीय निवेश ढांचे के तहत किसी निजी भारतीय समूह के साथ भूटान का पहला मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, जिसे डीजीपीसी के माध्यम से भूटानी नियंत्रण बनाए रखते हुए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रिलायंस पावर, ड्रुक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स की सहायक कंपनी ग्रीन डिजिटल के साथ मई, 2025 के अपने संयुक्त उद्यम के तहत, पश्चिमी और मध्य भूटान में अब तक के सबसे बड़े सौर निवेश करने जा रही है। 500 मेगावाट के सौर फार्म डेवलप करने के वास्ते अनिल अम्बानी के रिलायंस पावर ने एक दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) के लिए एक वाणिज्यिक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं, और ईपीसी निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है।

रिलायंस पावर 2026 के अंत तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगा और 2027 के मध्य तक 500 मेगावाट पूरी क्षमता से चालू हो जाएगी। यह परियोजना भूटान में जलविद्युत के अलावा पहली बार बड़े पैमाने अक्षय ऊर्जा के संतुलन की रणनीति को दर्शाता है। इस लक्ष्य के लिए डीएचआई के साथ रिलायंस पावर के अक्तूबर, 2024 के रणनीतिक समझौते में, मध्य भूटान में 770 मेगावाट की चमखरछु-I रन-ऑफ-रिवर परियोजना भी शामिल है। चमखरछु-I परियोजना भारत को भूटान के जलविद्युत निर्यात को बूस्टर डोज़ देगी, और संभवतः 2030 के दशक की शुरुआत तक भारत को अपनी पहली बिजली आपूर्ति शुरू कर देगी।

टाटा पावर ने भूटान में अपनी उपस्थिति भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान के सहयोग से मजबूत की, जिसका समापन जुलाई, 2025 में हुआ, जब उसने खोलोंगछू हाइड्रो पावर लिमिटेड (केएचपीएल) में 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की। त्राशियांगत्से में स्थित यह परियोजना, डीजीपीसी के साथ संयुक्त रूप से विकसित भूटान के सबसे तकनीकी रूप से जटिल उपक्रमों में से एक है। इसके वित्तपोषण के लिए, केएचपीएल ने एक ऋण प्राप्त किया। वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही में भारत के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 48 बिलियन (लगभग 580 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का सावधि ऋण प्राप्त होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्माण पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ आगे बढ़ सके। अनुमानित पांच वर्षों के निर्माण के साथ, 600 मेगावाट की यह परियोजना 2030-2031 के आसपास चालू होने वाली है।

जून, 2025 में जारी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के अनुसार, भूटान का लक्ष्य 2040 तक अपनी कुल स्थापित क्षमता को 25 गीगावाट तक बढ़ाना है। भूटान का लक्ष्य 20 गीगावाट हाइड्रो से, और 5 गीगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा से विद्युत का दोहन करना है।

अभियान

धड़कनों के बीच छिपा साहस

मकर संक्रांति की हल्की ठंडक वाली वह सुबह अलवार के बाहरी हिस्से में बसे शांत मोहल्ले में जैसे हमेशा की तरह शुरू हुई थी। आसमान पर धीरे-धीरे चढ़ती धूप और घर-घर से उड़ती तिल-गुड़ की खुशबू इस बात का संकेत दे रही थी कि त्योहार अपने पूरे उल्लास पर है। बाहर से देखने पर यह दिन बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन इस साधारण से दिन के भीतर एक ऐसा रोमांच छिपा था जिसे बाद में लोग दबी आवाज़ में एक किंवदंती की तरह सुनाने लगे।

आजाद पूरे देश की आज़ादी का प्रतीक बन चुके थे। अंग्रेज सरकार के लिए वह सिर्फ एक विद्रोही नहीं, बल्कि असहनीय चुनौती थे। कई दिनों से सीक्रेट एजेंट और पुलिस टुकड़ियाँ उनका पीछा कर रही थीं। वे अपने हर कदम पर खतरे का बोझ महसूस कर रहे थे। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अंग्रेज गुप्तचर उनके पीछे हैं और दूरी तेजी से कम होती जा रही है।

संकरी गलियों, पेड़ों की आड़, और भीड़ के बीच खुद को बदलते हुए आजाद दौड़ रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिमाग शांत। वह जानते थे कि यदि उन्हें बचना है तो किसी भरोसेमंद इंसान की छत के नीचे जल्द से जल्द पहुंचना होगा। ऐसे में उन्हें सिर्फ एक घर याद आया—उनके पुरानी दोस्त का घर, जिसे वे बेहद विश्वास करते थे। वे किसी तरह पीछा छूटता हुआ उस घर के आंगन में दाखिल हुए, दरवाजा हल्के से खटखटाया और तेजी से भीतर आ गए।

अंदर उनके मित्र ने बिना कोई सवाल किए उन्हें एक खाली कोठरी में छिपा दिया। आजाद की हथेलियाँ पसीने से भीगी थीं, लेकिन चेहरा दृढ़ था। परंतु किस्मत शायद उस सुबह अलग करवट लिए बैठी थी। किसी भेदिए ने पुलिस को खबर कर दी कि आजाद शायद इसी मोहल्ले में हैं। पुलिस दल ने पूरे इलाके को घेर लिया और कुछ ही देर बाद वही घर उनके घेरे में था। दरवाजे पर दस्तक इतनी तीखी थी कि घर का वातावरण एक पल में तनाव से भर गया। पुलिस का स्वर कठोर था—"तलाशी चाहिए! हमें खबर है कि चंद्रशेखर आजाद यहीं छिपे हुए हैं।" घर का मालिक बाहर आया। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था लेकिन उसका चेहरा स्थिर था। उसने कहा, "मेरे यहां कोई नहीं है।" पर पुलिस को उस पर भरोसा नहीं था। घर को चारों तरफ से घेरे पुलिसवाले भीतर घुस आए, हर कमरे को टटोला जाने लगा।

अंदर कोठरी में छिपे आजाद अपने हर कदम की आहट सुन रहे थे। उन्हें पता था कि जरा सी चूक उन्हें पकड़वा सकती है। उनका मित्र दरवाजे पर अड़ा हुआ पुलिस को समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हालत नाजुक होती जा रही थी। तभी घर की बहादुर और चतुर महिला, जिसने अब तक सिर्फ स्थिति को समझने में वक्त लिया था, अचानक आगे आई। उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता और तेज था जिसे देखकर आजाद तक का मन आश्वस्त हो गया।

महिला ने पल भर सोचा, फिर उसने अपनी आवाज़ इतनी ऊँची कर दी कि घर के बाहर तक सुनाई दे। वह उसी कमरे की ओर देखती हुई जोर से बोली—"अरे ओ! तुम कब तक बच्चों की तरह भीतर छिपे रहोगे? आज संक्रांति है! यह मिठाई की टोकरी उठाओ और चलो मेरे साथ, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी है। काम धंधा करने का भी शऊर नहीं है तुम्हें!"

उसकी आवाज़ इतनी स्वाभाविक और घर के सामान्य शोरगुल वाली थी कि यदि किसी को शक भी होता, तो वह तुरंत खत्म हो जाता। आजाद तुरंत समझ गए कि यह कोई डांट नहीं, बल्कि जीवनदान देने वाली एक चतुर रणनीति है। अगले ही क्षण उन्होंने बिना एक शब्द बोले तुंरत मिठाई की टोकरी उठाई, सिर पर रखी, और सामान्य नौकर की तरह उस महिला के पीछे-पीछे चलते हुए दरवाजे से बाहर आ गए।

बाहर पुलिसवाले अभी भी पूछताछ में उलझे थे। किसी की नजर उन पर नहीं गई। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि जिस इंसान को वे खोज रहे हैं, वह उनके ठीक सामने, एक साधारण से नौकर के वेश में, मिठाई की टोकरी उठाए गुजर रहा है। महिला के चेहरे पर इतनी सहजता थी कि वह पल ही पूरी परिस्थिति को धुंधला कर गया।

कुछ कदम दूर जाकर महिला रुकी, आजाद को धीमे स्वर में संकेत किया और फिर सामान्य सी शैली में अपने घर लौट गई। आजाद उसी राह से आगे बढ़ते गए—न कोई मिठाई बंटी, न कोई त्योहार मनाया गया। यह पूरा उत्सव केवल एक अद्भुत छलावा था—देशभक्ति और सूझबूझ का उत्सव।

जब वे काफी दूर निकल आए, तभी उन्होंने राहत की एक शांत सांस ली। वह टोकरी उन्होंने वहां छोड़ दी और फिर जंगलों की ओर मुड़कर अपने सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच गए। उस दिन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की गाथा में एक और अद्भुत अध्याय जुड़ गया—एक ऐसी महिला का साहस, जिसने अपनी चतुराई से देश के सबसे बहादुर क्रांतिकारी की जान बचा ली।

उस घटना के बाद वर्षों तक उस मोहल्ले में जब भी मकर संक्रांति आती, लोग तिल-गुड़ के साथ एक और कहानी सुनाते—एक ऐसी कहानी, जिसमें तिल-गुड़ की मिठास के भीतर छिपा था आजाद का बच निकलना और एक साधारण महिला का असाधारण साहस।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

बिजनौर की मासूम के साथ दरिंदगी की दिल दहला देने वाली कहानी: चॉकलेट का लालच देकर 67 साल के हैवान ने रौंद दी बचपन की पवित्रता

(जीएनएस)। बिजनौर में 67 साल के बुजुर्ग को रेप केस में अरेस्ट किया है। बुजुर्ग पर 8 साल की मासूम से दरिंदगी का आरोप लगा है। स्कूल जा रही बच्ची को उसने चॉकलेट का लालच दिया। फिर उससे रेप किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। आरोप है कि यहां 8 साल की मासूम को चॉकलेट का लालच देकर 67 साल के बुजुर्ग शाहिद ने उससे दरिंदगी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला बिजनौर के नगीना कस्बे का है। दरअसल, यहां एक मोहल्ले की एक आठ साल की छोटी बच्ची रोजाना स्कूल जाती थी। कभी-कभी शाहिद उसे टाफी, चाकलेट भी दे देता था। बच्ची यूकेजी में पढती है। गुरूवार को शाम चार बजे जब बच्ची अपने घर पहुंची तो उसके पास कई सारी टॉफी और दस रुपये का नोट भी था। बच्ची की मां ने बच्ची से टाफी और रुपये के बारे में पूछा तो बच्ची ने जो बताया वो सुन कर मां सन्न रह गई। उसकी आखों के आगे अंधेरा छा गया। बच्ची ने अपनी मां को बताया कि स्कूल जाते समय दाढ़ी

वाले अंकल उसे टॉफी और चॉकलेट कभी कभी नमकीन और बिस्कुट भी देते हैं। और उसके साथ गंदी बात भी करते हैं। बच्ची के द्वारा यह सब बताने पर मां ने बच्ची को दाढ़ी वाले अंकल के पास ले कर चलने को कहा। बच्ची मां के साथ बुजुर्ग शाहिद के पास पहुंची तो दोनों को देख कर शाहिद घबरा गया। अपनी उम्र का वास्ता देकर गलती मानते हुए चुप रहने को कहने लगा। लेकिन बच्ची की मां ने हंगामा करते हुए फोन कॉल करके 112 पुलिस बुला ली।

शाहिद को बुरा भला कहते हुए खरी खोटी भी सुनाई। फिर पुलिस शाहिद को अपने साथ थाने ले आई। महिला ने नगीना थाना पुलिस से शाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत दी है। जिस पर कारवाई करते हुए पुलिस ने दुष्कर्म, अश्लीलता करने और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।

बच्ची का पति उत्तराखंड में काम करता है

महिला ने बताया कि उसका पति उत्तराखंड में रहकर काम करता है। वह नगीना में रह कर अपने बच्चों की देखरेख कर रही है। स्कूल आने-जाने के समय मेरी बेटी को टॉफी और खाने की चीजें देकर लुभाता था और उसकी कम उम्र व मासूमियत का फायदा उठा कर अश्लील हरकतें और दुष्कर्म करता था। बच्ची को दर्द होने पर पूछने पर उसके द्वारा सब बताए जाने पर उसको भी मानसिक आघात लगा है।

मामले में क्या बोले नगीना के सीओ

पुलिस ने शाहिद के खिलाफ दुष्कर्म, अश्लीलता करने, पाक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हैवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नगीना के सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि इस केस का फास्ट ट्रैक अदालत में ट्रायल कराया जाएगा, ताकि अदालत दोषी को शीघ्र सजा सुनाकर मासूम बच्ची के साथ इंसाफ कर सके।

रिटायर्ड फौजी की संदिग्ध मौत: शरीर पर चोट के निशान, पत्नी की शिकायत पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज

(जीएनएस)। शिमला। राजधानी के एक मोहल्ले में रहने वाले सेना से सेवानिवृत्त सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने परिवार और स्थानीय समुदाय में भारी चिंता पैदा कर दी है। 12 नवंबर की रात को नशे की हालत में घर लौटे संदीप कुमार (आयु-— अनुमानित) की अगले दिन सुबह मौत हो गई। इलाज के क्रम में उनके शरीर पर गंभीर चोटों, खरोंचों और खून के धब्बों का पता चला, जिससे परिजन आशंकित हैं कि किसी प्रकार की मारपीट या बाहरी चोटें उनकी मौत का कारण बन सकती हैं। जवान रहते हुए देश की सेवा कर चुके इस व्यक्ति के निधन पर पुलिस ने मृतक की पत्नी कृष्णा देवी की शिकायत के आधार पर गैर-इरादतन हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों और अस्पताल के बयानों के मुताबिक, 12 नवंबर की रात संदीप घर पहुंचे तो उनकी नाक से खून बह रहा था तथा कपड़ों और हाथों पर भी खून के दाग थे। उनकी पत्नी ने तत्काल रिहैब-सेंटर के कर्मियों को घटना की जानकारी दी और रात के शुरुआती घंटे में ही सेंटर के लोग उन्हें इलाज के लिए लेकर गए। सुबह बाद में रिहैब-सेंटर ने कृष्णा देवी को सूचित किया कि संदीप की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक जाँच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव बाद में आईजीएमसी भेजा गया जहाँ पर अस्पताल

की टीम ने उन्हें मृतक घोषित करते हुए आगे की चिकित्सीय प्रक्रिया शुरू की।

आईजीएमसी में पोस्टमार्टम से पहले की गई प्राथमिक चिकित्सा-जाँच में डॉक्टरों ने उनके शरीर पर कई प्रकार की चोटें, खरोंचें और नीले निशान दर्ज किए। इन चोटों को देखते हुए पोस्टमार्टम एवं विष-विश्लेषण के लिए सैंपल लिये गए हैं और अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का वैज्ञानिक निष्कर्ष सामने आएगा। हालांकि परिवार का कहना है कि चोटों की गंभीरता को देखते हुए यही आशंका जताई जा रही है कि घर लौटने से पहले किसी ने उनके साथ मारपीट की होगी, जिससे हालत बिगड़कर मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर मामले की गहन तहकीकात शुरू कर दी है। थाना सदर के SHO के नेतृत्व में जांच-टीम को घटनास्थल, रिहैब-सेंटर तथा निजी अस्पताल के कर्मियों से पूछताछ के आदेश दिए गए हैं। पुलिस के आदेशों में रिहैब-सेंटर में संदीप के रहने और वहां से घर आने तक की गतिविधियों, सेंटर में उपस्थित कर्मियों के संचार रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, निजी अस्पताल के रिकॉर्ड और संदीप के चिकित्सीय इतिहास को प्राथमिकता से खंगाला जा रहा है। वहीं परिवार और गांव के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी बाहरी व्यक्ति की गलत हरकत तो नहीं हुई और क्या कोई परिचित या अज्ञात व्यक्ति घटना से जुड़ा है। घटना को और जटिल बनाने वाला तथ्य यह भी है कि मृतक लंबे समय से शराब की लत से जूझ रहे थे और हाल में उनका उपचार रिहैब-सेंटर तथा आईजीएमसी के मनोरोग वार्ड में भी चल रहा था। पुलिस ने कहा है कि यह मेडिकल इतिहास भी जांच का हिस्सा होगा ताकि स्पष्ट हो सके कि मौत में शराब-सम्बंधी जटिलताएँ, पूर्व स्वास्थ्य स्थितियाँ या किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा किस हद तक जिम्मेदार रही। साथ ही पारिवारिक रिकॉर्ड, रिहैब-सेंटर के दर्ज गतिविधि-रेकॉर्ड और चिकित्सीय दस्तावेजों की मिसमैच की स्थिति में भी कानूनी पहल होगी।

थाना प्रभारी ने परिवार को आश्वस्त किया है कि मामले की निष्पक्ष और तेज़ जांच होगी और आठ-दस दिनों में प्रारम्भिक निष्कर्ष साझा करने का प्रयास किया जाएगा, जबकि अंतिम परिणाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक परीक्षण के बाद ही उपलब्ध होगा। पुलिस ने कहा कि यदि जांच में किसी भी व्यक्ति का उल्लंघन या अपराध सिद्ध होता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को कानून के तहत कठोर दंड दिलाया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण, सामाजिक संगठनों और पूर्व सैनिकों के साथियों ने भी अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतक के परिजन न्याय की अपील कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि सत्य जल्द ही सामने आएगा। स्थानीय प्रशासन ने भी मामले की नजदीकी निगरानी करते हुए कहा है कि संवेदनशीलता के साथ जांच पूरी करायी जाएगी ताकि परिजन व समुदाय को सांत्वना मिल सके और किसी भी तरह की अफवाह या तनाव को बढ़ने से रोका जा सके।

फियो ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापार राहत उपायों - निर्यात प्राप्ति अवधि का विस्तार, अग्रिम भुगतान पर वस्तुओं को भेजने की अवधि में विस्तार; विशिष्ट प्रभावित क्षेत्रों पर ऋण चुकौती के बोझ को कम करना और निर्यात ऋण चुकौती में छूट - का स्वागत किया

(जीएनएस)। नई दिल्ली : फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्यात प्राप्ति अवधि को नौ महीने से बढ़ाकर पंद्रह महीने करने और निर्यात पर अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर वस्तुओं को भेजने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने के निर्णय का स्वागत किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान स्थगन या स्थगन के माध्यम से विशिष्ट प्रभावित सेक्टरों पर ऋण चुकौती के बोझ को कम किया है और ऋणदाताओं को

कार्यशील पूंजी सुविधाओं में 'आहरण शक्ति' की पुनर्गणना करने की अनुमति भी प्रदान की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात ऋण चुकौती अवधि में भी छूट दी है और ऋणदाताओं को 31 अगस्त, 2025 को या उससे पहले प्राप्त पैकिंग ऋण सुविधाओं को, जहाँ वस्तुओं को भेजना संभव नहीं था, किसी भी वैध वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से समाप्त करने की अनुमति है।

फियो के अध्यक्ष श्री एस. सी. रल्हन ने कहा, "इस विस्तार से निर्यात व्यापार को बड़ी राहत मिलेगी। निर्यातक विदेशी खरीदारों को बेहतर ऋण अवधि प्रदान कर सकेंगे। इस व्यापार-समर्थक घटनाक्रम के कारण व्यापार संबंधी अनुपालन मज़बूत होगा। भारतीय निर्यातकों को अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर वस्तुओं की शिपमेंट के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। सावधि ऋण और पैकिंग ऋण से संबंधित राहत उपायों से निर्यातक अपनी तरलता का उचित प्रबंधन कर सकेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि यह विस्तार कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप हो सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। फियो ने आश्वासन दिया कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यातक देश के बैंकिंग नियामक से उचित समर्थन के माध्यम से अपने निर्यात को बढ़ा सकें।

जगुदन स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के जगुदन स्टेशन यार्ड में 16.11.2025 (रविवार) को ब्रिज संख्या 982 के पुनर्निर्माण कार्य के संबंध में ब्लॉक लिया जा रहा है। जिसके कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जो निम्नानुसार हैः-

आंशिक रद्द ट्रेनेंः

1. दिनांक 16.11.2025 की ट्रेन संख्या 20959/20960 वलसाड-वडनगर-वलसाड एक्सप्रेस वडनगर और गांधीनगर कैपिटल के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
2. दिनांक 16.11.2025 की ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस

साबरमती-आबूरोड के बीच तथा दिनांक 17.11.2025 की ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस आबूरोड-साबरमती के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

रिशेड्यूल ट्रेनेंः

1. दिनांक 16.11.2025 की ट्रेन संख्या 20485 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस जोधपुर से 2 घंटे रिशेड्यूल होगी।
2. दिनांक 16.11.2025 की ट्रेन संख्या 69207 गांधीनगर कैपिटल–वरेठा मेमू गांधीनगर कैपिटल से 01 घंटा रिशेड्यूल होगी।

राजकोट-पोरबंदर ट्रेन को माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया एवं श्री अर्जुन मोढवाडिया ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ

(जीएनएस)। डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री, भारत सरकार, श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया, माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – गुजरात सरकार एवं राजकोट के कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा 14 नवम्बर, 2025 (शुक्रवार) को राजकोट रेलवे स्टेशन से राजकोट-पोरबंदर के बीच चलने वाली शुरूआती स्पेशल ट्रेन (Inaugural Special) को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया की ट्रेन नंबर 09561 राजकोट-पोरबंदर शुरूआती स्पेशल, राजकोट स्टेशन से सुबह 10.30 बजे चली। डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री, भारत सरकार, श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया, माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – गुजरात सरकार एवं अन्य महानुभावों ने राजकोट-पोरबंदर शुरूआती स्पेशल (Inaugural Special) में राजकोट से बैठकर पोरबंदर तक की यात्रा की। राजकोट-पोरबंदर सेक्शन के बीच आने वाले भावनगर मंडल के सभी स्टेशनों पर डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा मामले और

खेल मंत्री, भारत सरकार, श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया, माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – गुजरात सरकार का स्थानीय प्रतिनिधियों एवं आम जनता द्वारा स्वागत किया गया तथा ट्रेन चलने की खुशी व्यक्त की गई एवं आभार प्रकट किया गया ।

राजकोट - पोरबंदर ट्रेन के शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय राज्यसभा सांसद श्री रामभाई मोकरिया, माननीय सांसद राजकोट श्री परशोत्तम रुपाला, माननीया सांसद जामनगर श्रीमती पूनमबेन माडम, जिला अध्यक्ष पोरबंदर (भाजपा) श्रीमती चेतनाबेन तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पोरबंदर श्री पर्वतभाई परमार, जिला प्रभारी पोरबंदर श्री प्रदीपभाई खेमानी एवं अन्य गणमान्य अतिथि शामिल हुए।

भावनगर मंडल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी और श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया जी ने उपस्थित यात्रियों एवं आम जनता को संबोधित किया।

भावनगर रेलवे मंडल पर ट्रेन के स्वागत का मुख्य कार्यक्रम पोरबंदर रेलवे स्टेशन पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर पोरबंदर रेलवे स्टेशन पर मुख्य अतिथीगण के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इनके अलावा मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा एवं उनकी टीम तथा रेलयात्री, आम जनता एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

ट्रेन नंबर 59561 राजकोट-पोरबंदर पैसेन्जर दैनिक 15.11.2025 से प्रतिदिन नियमित रूप से अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी। यह ट्रेन राजकोट स्टेशन से सुबह 8.35 बजे प्रस्थान करेगी एवं 13.15 बजे पोरबंदर स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन नंबर 59562 पोरबंदर-राजकोट पैसेन्जर दैनिक 15.11.2025 से प्रतिदिन नियमित रूप से अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी। यह ट्रेन पोरबंदर से 14.30 बजे प्रस्थान करेगी एवं 18.55 बजे राजकोट स्टेशन पहुंचेगी।

ट्रेन नंबर 59564 पोरबंदर-राजकोट पैसेन्जर (सप्ताह में 5 दिन, गुरूवार और रविवार को छोड़कर) ट्रेन 15.11.2025 से पोरबंदर स्टेशन से सुबह 7.50 बजे प्रस्थान करेगी एवं 12.35 बजे राजकोट स्टेशन पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन नंबर 59563 राजकोट-पोरबंदर पैसेन्जर (सप्ताह में 5 दिन, बुधवार और शनिवार को छोड़कर) ट्रेन 16.11.2025 से राजकोट स्टेशन से दोपहर 14.50 बजे प्रस्थान करेगी एवं 20.30 बजे पोरबंदर स्टेशन पहुंचेगी।

उपरोक्त सभी ट्रेनें अपनी यात्रा के दौरान भक्तिनगर, रीबडा, गोंडल, वीरपुर, नवागढ़, जेतलसर, धोराजी, उपलेटा, पानेली मोटी, जाम जोधपुर, बालवा, काटकोला, वांसजालिया और राणावाव स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेंगी।

अक्टूबर माह में वडोदरा मंडल की उपलब्धियां,ऑटो ट्रेक्टर का हुआ पहली बार लदान,टिकट चेकिंग में 2.22 करोड़ की अब तक की सर्वोच्च वसूली

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने अक्टूबर माह में यात्री सेवा, माल लदान,टिकट जांच, संरक्षा, यात्री सुविधाओं आदि के क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रदर्शन हासिल किया। ये उपलब्धियां पश्चिम रेलवे के के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के गतिशील नेतृत्व और बहुमूल्य मार्गदर्शन में संभव हुई हैं।

वडोदरा मंडल द्वारा दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीज़न के दौरान यात्रियों की सुविधा और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। मंडल द्वारा परिचालित नियमित एवं 6 स्पेशल ट्रेनों के 19 फेरों के जरिये लगभग 30 लाख से ज्यादा यात्रिओं ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में अपने गंतव्य तक यात्रा की है। वडोदरा मंडल द्वारा मऊ , गोरखपुर , कोलकत्ता , कटिहार ,जयनगर और समस्तीपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलायी गयी।

नियमित ट्रेनों के साथ साथ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन मंडल के लिए चुनौती रहा, इन परिस्थितिओं में भी अक्टूबर माह में मंडल में ट्रेनों की समयपालनता 91. 73 प्रतिशत रही। वडोदरा मार्शलिंग यार्ड से पहली बार कर्नाटक राज्य के क्यारकोप के लिए ऑटो ट्रेक्टर का लदान कर सफलता पायी गयी।

अक्टूबर माह में मंडल ने माल लदान

के क्षेत्र में 1. 29 MT का माल लदान हासिल किया तो वही यात्री राजस्व के क्षेत्र में 56.24 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग के टिकट जांच कर्मचारियों की सतर्कता और मेहनत के परिणामस्वरूप 2.22 करोड़ की अब तक की सर्वोच्च वसूली दर्ज की गई है, जो नवंबर 2021 के पिछले रिकॉर्ड 1.94 करोड़ को पार कर गई है।

मंडल के लिए संरक्षा सर्वोपरि है , 41 रेल कर्मियों को सुरक्षित ट्रेन परिचालन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए सम्मानित किया। इन रेल कर्मियों को ड्यूटी के दौरान उनकी सजगता एवं सतर्कता के कारण अप्रिय घटनाओं को रोकने में उनके योगदान के लिए प्रमाण-पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया।

ट्रेन परिचालन में विफलताओं को कम करने और संरक्षा में वृद्धि के लिए मल्टी सेक्शन एक्सल काउंटर को सायन यार्ड में लगाया गया है। साथ ही महेमदाबाद स्टेशन के एलसी गेट संख्या 290 पर इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बैरियर के प्रतिस्थापन कार्य को पूरा किया गया। विश्वामित्री–जोगट सेक्शन के प्रतापनगर–डभोई स्टेशनों के बीच क्रॉसिंग सुविधा प्रदान करने और 'D' श्रेणी स्टेशन को 'B' श्रेणी स्टेशन में अपग्रेड करने के कार्य के तहत, कुंडेला स्टेशन पर नया सेंट्रलाइज़्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कमीशन कर दिया गया है।

पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल सेवा, संरक्षा और गति के मूल मंत्र को आत्मसात कर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

साबरमती रेलवे स्टेशन पर "वंदे मातरम्" प्रदर्शनी का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा साबरमती रेलवे स्टेशन पर "वंदे मातरम्" प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम, वीर स्वतंत्रता सेनानियों तथा राष्ट्रभक्ति की गौरवशाली परंपरा को जन–जन तक पहुँचाना है। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज़, ऐतिहासिक चित्र, वीर सेनानियों के प्रेरक जीवन प्रसंग, देशभक्ति साहित्य तथा विभिन्न कला–कृतियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। विशेष आकर्षण के रूप में "वंदे मातरम्" गीत की रचना, उसका ऐतिहासिक महत्व तथा उससे जुड़े प्रमुख प्रसंगों को सुंदर, प्रभावी व दर्शनीय रूप में प्रस्तुत किया गया है।

"वंदे मातरम्" केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रप्रेम और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अमर प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में इस गीत ने देशवासियों में अदम्य उत्साह, साहस और एकता का संचार किया। आज भी "वंदे मातरम्" हमें राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित में योगदान देने की प्रेरणा प्रदान करता है।

यह प्रदर्शनी देशभक्ति, इतिहास और संस्कृति से ओत–प्रोत अनुभव प्रदान करती है तथा सभी आयु वर्ग के आगंतुकों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली गाथा से जोड़ने का उत्कृष्ट मंच सिद्ध हो रही है।

भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं जनजातीय गौरव सप्ताह का भावनगर मंडल में उत्साहपूर्वक आयोजन

(जीएनएस)। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर पूरे देश में 01 नवम्बर से 15 नवम्बर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में भावनगर मंडल में आज, दिनांक 14 नवम्बर 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास, उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मंडल सभागार में "जनजातीय गौरव सप्ताह" अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात उनके जीवन, संघर्ष एवं स्वतंत्रता संग्राम

में अमूल्य योगदान पर आधारित प्रेरक वृत्तचित्र प्रदर्शित किया गया।

अपने संबोधन में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष कर आदिवासी समाज को एकजुट किया, बल्कि समाज सुधार एवं राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए भी विशिष्ट योगदान दिया। उनका सम्पूर्ण जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान और देशभक्ति का प्रेरक प्रतीक है, जिससे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी।

सेमिनार के दौरान वक्ताओं द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तथा आदिवासी समाज के उत्थान हेतु किए गए उनके कार्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों को उनके जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायी शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में शाखा अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ट्रेड यूनियन एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम का सफल आयोजन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन के मार्गदर्शन में तथा सहायक कार्मिक अधिकारी (I) श्री वाई. राधेश्याम के समन्वय से किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्मिक विभाग के मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक श्री शैलेश कुमार परमार द्वारा किया गया।

बांद्रा टर्मिनस-बरौनी एक्सप्रेस पिपराइच स्टेशन पर नहीं रुकेगी

(जीएनएस)। पूर्वोत्तर रेलवे के पिपराइच स्टेशन पर चल रहे नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 16 नवंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी एक्सप्रेस पिपराइच स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इसी प्रकार, 18 नवंबर, 2025 को बरौनी से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19038 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस पिपराइच स्टेशन पर नहीं रुकेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त परिवर्तन को ध्यान में रखकर यात्रा करें।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं दुर्गापुरा के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त यात्री यातायात की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस एवं दुर्गापुरा स्टेशन के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 09730/09729 बांद्रा टर्मिनस-दुर्गापुरा सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09730 बांद्रा टर्मिनस-दुर्गापुरा सुपरफास्ट स्पेशल सोमवार, 17 नवंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 10:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05:30 बजे दुर्गापुरा पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09729 दुर्गापुरा-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल रविवार, 16 नवंबर, 2025 को

दुर्गापुरा से 12:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर और बनस्थली निवाई स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09730 की बुकिंग 15 नवम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर में उपचुनाव का रोमांचक मुकाबला दोनों सीटों पर पुराने दावेदारों ने ही दोहराई सफलता

(जीएनएस)। जम्मू-कश्मीर की दो अहम विधानसभा सीटों—बडगाम और नगरोटा—पर हुए उपचुनावों के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि जनता ने इस बार बदलाव के बजाय भरोसे को प्राथमिकता दी है। शुक्रवार को घोषित नतीजों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने बडगाम सीट को फिर से अपने नाम किया, जबकि नगरोटा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एकतरफा जीत हासिल करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखा। दोनों दलों के उम्मीदवारों ने भारी अंतर से जीत दर्ज कर यह संदेश दिया कि स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ अभी भी उतनी ही मजबूत है।

बडगाम सीट से पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने 4,186 वोटों से जीत दर्ज की। इस सीट पर मुकाबला हमेशा से दिलचस्प रहा है, लेकिन इस बार वोटरों ने स्पष्ट रूप से पीडीपी में भरोसा जताया। बडगाम में पीडीपी को कुल 21,576 वोट मिले और दूसरे स्थान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस रही। खास बात यह है कि यह उपचुनाव तभी आवश्यक हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 के चुनाव में दो सीटों—बडगाम और गांदरबल—से जीत दर्ज करने के बाद बडगाम सीट छोड़ने का निर्णय लिया। उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर पीडीपी ने वापसी की और जनता ने भी इस वापसी को स्वीकार किया। दूसरी तरफ नगरोटा में बीजेपी की देवयानी राणा ने 24,647 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। उन्हें कुल 42,350 वोट मिले, जो यह दिखाता है कि यहां भाजपा का जनाधार बेहद मजबूत है। नगरोटा सीट उनके पिता देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी। देवयानी को टिकट दिए जाने के बाद यह माना जा रहा था कि उन्हें सहानुभूति के साथ-साथ भाजपा संगठन का पूरा समर्थन मिलेगा, और नतीजे ने इस आकलन को सही साबित कर दिया।

मतदान प्रतिशत के लिहाज़ से भी दोनों क्षेत्रों में स्थिति संतुलित रही। बडगाम में जहां 48 प्रतिशत वोट डाले गए, वहीं नगरोटा में मतदान का आंकड़ा 72 प्रतिशत तक पहुंचा। नगरोटा की इस उच्च भागीदारी ने देवयानी राणा की जीत को और अधिक मजबूत बना दिया।

जीत के बाद देवयानी राणा ने भावुक होते हुए कहा कि नगरोटा ने उनके पिता को जिस तरह आशीर्वाद दिया था, आज उसी स्नेह और विश्वास के साथ उन्हें भी अपनाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो जीत के लिए ही लड़ती है, और नगरोटा इसका ताज़ा उदाहरण है। इन दोनों उपचुनावों ने यह साबित किया कि जम्मू-कश्मीर की स्थानीय राजनीति अभी भी परिवारों की विरासत, दलों की जमीनी पकड़ और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत साख पर ही घूमती है। बडगाम में पीडीपी की वापसी और नगरोटा में बीजेपी की लगातार पकड़ से यह भी साफ है कि दोनों दल अपने-अपने क्षेत्रों में अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। उपचुनाव का यह संतुलित नतीजा आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक दिशा और बड़े चुनावों की रणनीति को भी प्रभावित करेगा।

छत्तीसगढ़ में किसानों और आम जनता के लिए बड़े फैसले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में ऐतिहासिक

(जीएनएस)। छत्तीसगढ़ में मंगलवार का दिन किसानों, आवास योजनाओं के लाभार्थियों और खेल जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर राज्य के लाखों किसानों, शहरी एवं ग्रामीण परिवारों और उभरते खिलाड़ियों पर पड़ेगा। यह बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उसमें राज्य की आर्थिक संरचना, मंडी व्यवस्था, आवास योजनाओं और खेल ढांचे को मजबूत करने की दूरगामी दृष्टि दिखाई दी।

बैठक में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि खरीफ और रबी दोनों विपणन मौसमों में दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत पहले की ही तरह जारी रहेगी। अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मसूर, सरसों जैसी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था ने पिछले वर्षों में किसानों को बाजार में मजबूती दी है। इस बार भी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहे, जिससे किसानों की उपज का उचित मूल्य उन्हें बिना किसी शोषण के मिल सके। इससे हजारों किसानों की आर्थिक सुरक्षा और आय स्थिरता पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

इसके बाद राज्य के प्रशासनिक ढांचे को सुचारु बनाने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में मिलाया जाएगा, जबकि बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में शामिल किया जाएगा। यह बदलाव भविष्य में योजनाओं के बेहतर समन्वयन और तेजी से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

धान खरीदी को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के संचालन के लिए जो 15,000 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी बैंकों को दी गई थी, उसे आगामी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ की गारंटी राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि धान खरीदी की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलती रहे। आवास योजनाओं में लंबे समय से लंबित एक मुद्दे को भी इस बैठक में समाधान मिला। राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नया रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना में नए प्रावधान शामिल किए गए, जिनसे अविक्रित भवनों की बिक्री को आसान बनाया गया है।

बागपत के स्कूल में अमानवीय हरकत से मचा हड़कंप, बच्चों को पेशाब मिलाकर पानी पिलाए जाने से फैला तनाव, पुलिस तैनात

(जीएनएस)। बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ढिकोली गांव स्थित एक प्राथमिक विद्यालय से ऐसा भयावह मामला सामने आया है, जिसने इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया। स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों को उनके ही सहपाठी कुछ नाबालिग छात्रों ने पानी की बोतल में पेशाब मिलाकर पिला दिया। यह हरकत इतनी अमानवीय, इतनी विचलित करने वाली थी कि जैसे ही बच्चों के परिजनों को इसकी जानकारी मिली, गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते स्कूल का माहौल तनाव, गुस्से और अविश्वास से भर उठा, और बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल के बाहर जमा हो गए।

पीड़ित बच्चों ने घर पहुंचते ही यह घटना बताई कि किस तरह एक समुदाय विशेष से जुड़े तीन नाबालिग साथियों ने उनकी पानी की बोतल में पेशाब मिलाया और उन्हें पीने के लिए मजबूर किया। इतनी दर्दनाक घटना सुनते ही परिजन बेकाबू हो उठे और तुरंत स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीड़ का गुस्सा बढ़ता गया, और स्कूल में अफरातफरी की स्थिति बनने लगी।

मौके पर जैसी स्थिति बनी, उसे संभालने के लिए चांदीनगर थाने के प्रभारी और खेकड़ा के क्षेत्राधिकारी रोहन चौरसिया अपनी टीम के साथ तुरंत पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने भारी भीड़ को शांत करने की कोशिश की, अभिभावकों को समझाया और भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कई बच्चों ने पुलिस और प्रधानाचार्य के सामने बयान दिया कि उन्होंने खुद तीन आरोपित छात्रों को बोतल में पेशाब भरते देखा था, जिसके आधार पर घटना की प्रारंभिक पुष्टि कर दी गई।

घटना से जुड़े एक अन्य पहलू ने मामला और गंभीर बना दिया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का एक युवक अक्सर स्कूल के आसपास देखा जाता है और बच्चों को भड़काने या गलत चीजें सिखाने में उसकी भूमिका संदिग्ध है। लोग इस युवक की गतिविधियों को लेकर पहले भी चिंता जता चुके हैं, और अब इस घटना के बाद उसकी भूमिका जांच के दायरे में आ गई है। पुलिस भी इस एंगल की जांच कर रही है कि कहीं बच्चों को ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए किसी बड़े की तरफ से उकसाया तो नहीं गया।

प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ित बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। पुलिस ने प्रधानाचार्य की लिखित शिकायत पर तीनों आरोपित बच्चों के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि कानून के तहत नाबालिग बच्चों पर सीधे मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी अभिभावकीय जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

सीओ रोहन चौरसिया ने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और जांच टीम सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्कूल में अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन हर आवश्यक कदम उठाएगा, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

गांव में अभी भी रोष है, माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, और लोग यह समझ नहीं पा रहे कि इतनी कम उम्र के बच्चे इतनी हैवानियत पर कैसे उतर आए। यह घटना समाज में बढ़ती नफरत, गलत दिशा देने वाले तत्वों और बच्चों के मानसिक वातावरण पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। पुलिस की जांच जारी है, और स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सच्चाई सामने आएगी और ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं दोहराई जाएगी।

गुरुग्राम को जाम से मिलेगी राहत, अंबेडकर चौक और दादी सती चौक पर दो नए फ्लाईओवर बनने की तैयारी

(जीएनएस)। गुरुग्राम की रोज़ाना की सबसे बड़ी परेशानी अब खत्म होने की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। शहर के दो बेहद व्यस्त और ट्रैफिक के बोझ से टूटते चौराहों—अंबेडकर चौक और दादी सती चौक—पर अब नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इस निर्णय से उन लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो रोज़ाना घंटों जाम में फंसकर अपना समय और ऊर्जा गंवाते हैं। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है और 30 नवंबर तक इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है।

गुरुग्राम में बीते कुछ वर्षों में आबादी और वाहन संख्या दोनों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन सड़क संरचनाएं इस गति से विकसित नहीं हो सकीं। नतीजा यह हुआ कि शहर के प्रमुख चौराहे, खास तौर पर अंबेडकर चौक और दादी सती चौक, दिन के अधिकांश समय ट्रैफिक से जाम रहते हैं। चाहे ऑफिस का समय हो या स्कूल का, इन दोनों स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और सिग्नल पर कई-कई चक्र तक रुकना पड़ता है। शहर के निवासी लंबे समय से इन चौराहों पर फ्लाईओवर की मांग कर रहे थे ताकि यातायात का भार ऊपर से निकले और नीचे का मार्ग बिना रुकावट चलता रहे।

जीएमडीए की योजना के मुताबिक, अंबेडकर चौक पर बनने वाले फ्लाईओवर पर लगभग 51.68 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि दादी सती चौक का फ्लाईओवर लगभग 59 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। दोनों फ्लाईओवरों के लिए ए.कॉम कंपनी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। पहले बनाए गए डिजाइनों में कुछ बदलाव किए गए ताकि संरचना अधिक सुरक्षित और दृश्यता के लिहाज़ से बेहतर हो सके। इन्हीं बदलावों के बाद डीपीआर को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा गया था, जहां विशेषज्ञों ने विस्तृत जांच की और अब उनकी समीक्षा रिपोर्ट जीएमडीए के पास पहुंच चुकी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में इन दोनों फ्लाईओवरों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण निर्माण में देरी हुई थी, लेकिन अब सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि 30 नवंबर तक दोनों कार्यों के टेंडर जारी कर दिए जाएंगे और टेंडर मिलते ही निर्माण तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। अंबेडकर चौक पर बनने वाला फ्लाईओवर गुरुग्राम-सोहना हाईवे की दिशा में वाहनों को ऊपर से ले जाएगा, जिससे सोहना रोड की ओर जाने वाले वाहनों को बिना रुकावट यात्रा का रास्ता मिल जाएगा। वहीं, दादी सती चौक पर फ्लाईओवर द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर ले जाएगा, जिससे नई रिहायशी कॉलोनियों वाले क्षेत्रों—विशेषकर सेक्टर-86, 87, 89 और 90—के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

वर्तमान में दोनों चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल आधारित व्यवस्था है और पीक ऑवर्स में यहां जाम की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि सामान्य दूरी तय करने में भी दोगुना समय लग जाता है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि सुबह का एक-एक मिनट उनके काम और समय सारिणी को प्रभावित कर देता है। लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद न सिर्फ ट्रैफिक का प्रवाह सुगम होगा, बल्कि नीचे की सड़कों पर दबाव कम होने से दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी।

अंतरराष्ट्रीय कोकीन सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई, दिल्ली एनसीआर और जयपुर में ईडी की तड़ातड़ छापेमारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार की सुबह एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 82.53 किलोग्राम कोकीन की तस्करी से जुड़े धनशोधन नेटवर्क की जांच के सिलसिले में ईडी ने दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक साथ पांच ठिकानों पर छापे मारे। सुबह लगभग सात बजे शुरू हुई इस कार्रवाई ने पूरे मादक पदार्थ गिरोह में खलबली मचा दी, क्योंकि एजेंसी की टीमें स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर रिकॉर्ड, उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक डाटा को अपने कब्जे में लेती रहीं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह मामला केवल कोकीन की एक खेप की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों में फैले एक विशाल और संगठित अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़ा है, जो भारत को उच्च-मूल्य वाली कोकीन का नया और तेजी से उभरता हुआ बाज़ार मानकर यहां तस्करी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ईडी को संदेह है कि आरोपी नेटवर्क न सिर्फ देश में सप्लाई चैन स्थापित कर रहा था, बल्कि तस्करी से अर्जित भारी भरकम धन को हवाला चैनलों के ज़रिए विदेशों में भी भेज रहा था। इन्हीं गतिविधियों की तह में जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलाशी अभियान शुरू किया है।

छापेमारी की कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखा गया और टीमें सीधे संदिग्धों के निवास व कारोबारी ठिकानों पर पहुँचकर तलाशी में जुट गईं। बताया जाता है कि कई जगहों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड, यात्रा दस्तावेज़ और संचार सामग्री बरामद की गई है, जिनकी जांच एजेंसी के विशेषज्ञ कर रहे हैं। इस ऑपरेशन का उद्देश्य उन सभी कड़ियों को जोड़ना है जिनके माध्यम से यह अंतरराष्ट्रीय गिरोह भारत में अपनी जड़ें जमा रहा था।

सूत्रों के अनुसार गिरोह के तार कई विदेशी नागरिकों, स्थानीय सप्लायर्स और आर्थिक फ़ायदे पहुँचाने वाले बिचौलियों से जुड़े होने की आशंका है। भारत आने वाली इस कोकीन की खेप की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अरबों रुपये आंकी गई है और इसके पीछे चल रहे नेटवर्क को अत्यंत पेशेवर और संगठित माना जा रहा है। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि तस्करों को किसने संरक्षण दिया, किसके बैंक खातों में यह पैसा गया और क्या इस मामले में किसी कारोबारी, एजेंट या स्थानीय समूह की भूमिका रही।

पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों में हाई-प्रोफाइल मादक पदार्थ तस्करी के कई बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें कोकीन, हेरोइन, चारस व एंफेटामिन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की भारी मात्रा पकड़ी गई है। एनसीबी, पुलिस और अब ईडी की लगातार कार्रवाई से साफ है कि भारत में सक्रिय विदेशी ड्रग कार्टेलों के खिलाफ एक समन्वित राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है। एजेंसियां यह भी मानती हैं कि वैश्विक मादक पदार्थ तस्करी के गिरोह भारत को अपनी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां बड़ी आबादी, तेज़ी से बढ़ती क्रय क्षमता और युवाओं के बीच नशे की बढ़ती खपत उन्हें आसान बाज़ार उपलब्ध कराती है। यह छापेमारी अभी जारी जांच का केवल एक चरण है। ईडी आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और नामों का पर्दाफाश कर सकती है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि इस मामले में कई और गिरफ्तारी एवं आर्थिक संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई आगे हो सकती है।

देशभर के किसानों के चेहरे फिर खिलेंगे, 19 नवंबर को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने से गांवों में उम्मीदों का नया उजाला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के करोड़ों किसान परिवारों के लिए 19 नवंबर का दिन एक बड़े उत्सव जैसा साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। यह किस्त सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में डाली जाएगी, जिससे रबी की बुआई के बीच उन्हें न सिर्फ आर्थिक संबल मिलेगा बल्कि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी राहत महसूस होगी। अब तक इस योजना के माध्यम से सरकार 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये की ऐतिहासिक राशि ट्रांसफर कर चुकी है, जिसने इसे देश की सबसे व्यापक और भरोसेमंद कल्याणकारी योजनाओं में से एक बना दिया है।

24 फरवरी 2019 को शुरू हुई इस योजना का बुनियादी उद्देश्य खेती-किसानी की अनिश्चितताओं के बीच किसानों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा देना था, ताकि वे बीज, खाद, उपकरण, सिंचाई और अन्य कृषि संबंधित खर्चों को बिना कर्ज़ के दबाव के पूरा कर सकें। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2,000-2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। यह डीबीटी प्रणाली इतनी पारदर्शी और तेज़ है कि किस्त जारी होने के कुछ ही मिनटों में देशभर से किसानों के पास संदेश आने लगते हैं कि उनकी राशि खाते में पहुंच गई है। योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई तकनीकी सुधार भी लागू किए हैं। किसानों की जमीन का रिकॉर्ड डिजिटली पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य किया गया है, बैंक खाते आधार से जुड़े हैं और ई-केवाईसी पूरा करना भी आवश्यक है। इन सभी कदमों से न सिर्फ योजना में पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों को स्वतः बाहर कर दिया गया है, जिससे वास्तविक किसानों को ही सहायता मिल रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, योजना से जुड़े लाभार्थियों में 25 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को मजबूत करता है। पीएम-किसान योजना की राशि का उपयोग किसान केवल कृषि कार्यों में ही नहीं कर रहे, बल्कि इसने उनके परिवार की सामाजिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई राज्यों से ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि किसान किस्त की राशि से अपने बच्चों की फीस जमा कर रहे हैं, घर का राशन खरीद रहे हैं या अचानक आई स्वास्थ्य समस्या से निपट रहे हैं। यह योजना धीरे-धीरे ग्रामीण परिवारों की जीवनरेखा बनती जा रही है।

कृषि मंत्रालय ने एक और बड़ी पहल की तैयारी की है—'किसान रजिस्ट्री' बनाने की। यह डिजिटल रजिस्ट्री भविष्य में किसानों की एकीकृत पहचान के रूप में काम करेगी, जिसके आधार पर वे विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना किसी लंबी प्रक्रिया और दस्तावेज़ी परेशानी के उठा सकेंगे। अभी एक किसान को कई योजनाओं में अलग-अलग आवेदन करने पड़ते हैं, लेकिन रजिस्ट्री बनने के बाद यह व्यवस्था सरल, पारदर्शी और सीधे किसान-केंद्रित हो जाएगी।

देश के कई इलाकों में किसान पहले से ही 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। रबी की फसल की तैयारियों के बीच किसानों का कहना है कि यह राशि उनके लिए समय पर मिलने वाला सहारा है, जिसकी बदौलत वे बुआई से लेकर खेतों की देखभाल तक के खर्च संभाल पाते हैं। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इस योजना को और मजबूत बनाने के लिए कुछ तकनीकी और प्रशासनिक सुधार भी लागू करेगी, ताकि इसका लाभ खेत-खेत और किसान-किसान तक निर्बाध रूप से पहुंच सके।

पाकिस्तान में अचानक लापता हुई कपूरथला की महिला श्रद्धालु, प्रकाश पर्व मनाने गई थी जांच में सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

(जीएनएस)। पंजाब के कपूरथला जिले से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन करने गई एक भारतीय महिला रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 4 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था पाकिस्तान गया था, लेकिन उसी जत्थे की सदस्य सरबजीत कौर वापस नहीं लौटीं। इससे सुरक्षा एजेंसियों से लेकर स्थानीय प्रशासन तक में हड़कंप मचा हुआ है।

सरबजीत कौर, जो डाकघर टिब्बा, गांव अमैनीपुर की रहने वाली हैं, जत्थे में शामिल होकर पाकिस्तान तो पहुंच गईं, लेकिन वापसी के समय उनका कोई अता-पता नहीं मिला। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान इमिग्रेशन में दाखिल किए गए फॉर्म में उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी—राष्ट्रीयता और पासपोर्ट नंबर—खाली छोड़ दिए थे। यह तथ्य जांच एजेंसियों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लग रहा है, क्योंकि यात्रा के दौरान ऐसे कॉलम खाली छोड़ना सामान्य नहीं होता। इससे संदेह गहरा हो गया है कि कहीं यह सब पहले से योजनाबद्ध तो नहीं था।

भारतीय इमिग्रेशन के अनुसार, कुल 1932 श्रद्धालु अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान गए थे। दस दिनों तक ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन करने के बाद जत्था वापस लौट आया। देर शाम तक 1922 श्रद्धालु भारत पहुंच चुके थे, जबकि चार धार्मिक सदस्य और तीन महिलाएं—जिनके घर में किसी की तबीयत खराब थी—पहले ही लौट आई थीं। कुल गणना में सिर्फ एक ही व्यक्ति गायब थी—सरबजीत कौर।

जब अधिकारियों ने लौटे हुए जत्थे की सूची मिलान की, तब यह खुलासा हुआ कि वह महिला ना तो किसी अन्य मार्ग से लौटीं और ना ही पाकिस्तान में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। इससे अब यह आशंका जताई जा रही है कि सरबजीत कौर स्वेच्छा से वहीं रुक गईं, या फिर किसी व्यक्ति या संगठन ने उन्हें रोक लिया। सीमा सुरक्षा बल (BSF), पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अब इस मामले की संयुक्त जांच कर रही हैं। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन को भी अलर्ट किया गया है और उनसे सरबजीत कौर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है। उनका मोबाइल फोन भी बंद बताया जा रहा है, जिससे लोकेशन ट्रैकिंग मुश्किल हो रही है। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि पिछले कई वर्षों में कुछ श्रद्धालु पाकिस्तान जाकर वहां बसने या किसी के प्रभाव में रहने के मामले सामने आए हैं।

हिंदी सिनेमा की अमर खूबसूरती कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में निधन, सात दशकों से अधिक फैला एक असाधारण सफर हुआ पूरा

(जीएनएस)। मुंबई। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की मशहूर और सदाबहार अभिनेत्री कामिनी कौशल का गुरुवार देर रात मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया। 98 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और इस प्रकार लगभग पूरे शताब्दी काल को अपने सौम्य व्यक्तित्व और अद्भुत अभिनय से महकाने वाली यह अद्वितीय अभिनेत्री अब इतिहास का हिस्सा बन गईं। परिवार के करीबी मित्र साजन नारायण ने बताया कि वह फरवरी में 99 वर्ष की होने वाली थीं और अंतिम दिनों तक पूरी तरह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता रही थीं। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का प्रवाह उमड़ पड़ा। करीना कपूर ने उनकी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा करते हुए उन्हें याद किया, वहीं आईफा अवॉर्ड्स और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी उन्हें भारतीय सिनेमा की एक चमकदार, बहुमुखी और अविस्मरणीय प्रतिभा बताया।

कामिनी कौशल का सफर किसी फ़िल्मी कथा से कम नहीं था। 1946 में चेतन आनंद की अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म 'नीचा नगर' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली युवा उमा कश्यप को उस समय कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित अभिनेत्री बन जाएँगी। लाहौर में 24 फरवरी 1927 को पैदा हुई इस प्रतिभाशाली युवती के पिता शिव राम कश्यप भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते थे और परिवार में ज्ञान तथा विनम्रता दोनों की विरासत थी। चेतन आनंद ने उमा को अभिनय के प्रस्ताव के साथ ही नया नाम 'कामिनी कौशल' दिया ताकि फिल्म की दूसरी कलाकार उमा से भ्रम न हो। यहीं से एक नई कलाकार का जन्म हुआ जिसने आने वाले वर्षों में बॉलीवुड के इतिहास को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया।

कामिनी कौशल ने ना केवल 1940 और 50 के दशक में सबसे अधिक फीस पाने वाली अभिनेत्रियों में स्थान बनाया, बल्कि दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर जैसे दिग्गजों की पहली पसंद बनकर रोमांटिक नायिका की छवि को नई परिभाषा दी। 'जेल यात्रा', 'दो भाई', 'आग', 'शहीद', 'नदिया के पार', 'जिद्दी', 'शबनम', 'आरजू' और अन्य कई फिल्मों में उनकी उपस्थिति ने अभिनय की सरलता को प्रतिष्ठा में बदला। 1954 में उन्होंने बिमल रॉय की 'बिराज बहू' में अपने करियर का श्रेष्ठ अभिनय दिया, जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। प्रेमचंद के उपन्यास 'गोदान' के फिल्म रूपांतरण में उनकी भूमिका भी आज तक याद की जाती है।

1960 के बाद उनके अभिनय का एक नया चरण शुरू हुआ, जब वह मनोज कुमार की 'उपकार' से माँ की भूमिकाओं में नज़र आने लगीं। केवल 40 वर्ष की आयु में वह माँ के किरदारों का प्रतीक बन गईं और इसी रूप में 'पूरब और पश्चिम', 'शोर', 'रोटी कपड़ा और मकान', 'संतोष', 'दस नंबरी', 'प्रेम नगर', 'महा चोर' जैसी फिल्मों में उनके किरदार अमिट रह गए। राजेश खन्ना, मनोज कुमार, धर्मेंद्र से लेकर बाद के दौर में शाहरुख खान और शाहिद कपूर के साथ भी उन्होंने पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 95 साल की उम्र में भी उन्होंने आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में अभिनय कर यह सिद्ध कर दिया कि कला कभी बूढ़ी नहीं होती।

टेलीविजन में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। ब्रिटिश धारावाहिक 'द ज्वेल इन द क्राउन' में आंटी शालिनी के रूप में उनकी भूमिका को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। 'चांद सितारे', 'वक्त की रफ्तार' और 'शन्नो की शादी' जैसे भारतीय टीवी धारावाहिकों में भी वह घरेलू दर्शकों की प्रिय बनी रहीं।

उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही भावनात्मक रही। 1948 में एक कार दुर्घटना में अपनी बहन की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने जीजा बीएस सूद से विवाह किया और दो बेटियों की सौतेली माँ बन गईं। बाद में उनके तीन बेटे—राहुल, विदुर और श्रवण—हुए। परिवार के प्रति उनकी निष्ठा और संतुलित जीवनशैली ने उन्हें उम्र भर सहज, संयमित और विनम्र बनाए रखा।

कामिनी कौशल के 76 वर्ष लंबे शानदार करियर में लगभग हर युग, हर शैली और हर पीढ़ी की छाप समाई हुई है। उनका निधन केवल एक अभिनेत्री का जाना नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक स्वर्णिम अध्याय का शांत अंत है। जिस युग में अभिनय तकनीकें बदल रही हैं और फिल्में लगातार नए प्रयोगों से गुजर रही हैं, वहाँ कामिनी कौशल जैसे कलाकार यह याद दिलाते हैं कि वास्तविक अभिनय, सरलता और संवेदना कभी पुरानी नहीं होती। उनका जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक युग का अंत है—एक ऐसा युग जिसकी चमक आज भी इतिहास के पन्नों पर अमर है।

कैद हुआ बलोचिस्तान: बंद ट्रेनों, थमी बसों और आसमान छूते हवाई किरायों के बीच लोगों की जिंदगी ठहरी

(जीएनएस)। क्वेटा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलोचिस्तान इन दिनों अभूतपूर्व परिवहन संकट की गिरफ्त में है। सुरक्षा खतरों, प्रशासनिक बंदिशों और संचार प्रतिबंधों ने मिलकर प्रांत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां आम लोगों की दैनिक आवाजाही लगभग असंभव हो गई है। रेल सेवाएं ठप हैं, बसें चलनी बंद हो गई हैं, निजी गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है और मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह बंद है। ऐसे में हवाई यात्रा ही एकमात्र सहारा बची है, लेकिन उसका किराया जिस तेजी से बढ़ा है, उसने पूरे प्रांत को परेशानियों के ऐसे दलदल में धकेल दिया है, जिसका अंत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा।

सामान्य दिनों में क्वेटा से कराची, लाहौर या इस्लामाबाद जाने वाली बसें और ट्रेनें हजारों यात्रियों की जरूरतें पूरी करती थीं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार मिल रहे इनपुट और हालिया घटनाओं के चलते प्रांतीय प्रशासन ने न केवल ट्रेनों का परिचालन रोक दिया, बल्कि पंजाब की ओर जाने वाली सड़कों पर निजी और सार्वजनिक वाहनों के चलने तक पर रोक लगा दी। परिणामस्वरूप, लाखों लोगों की दिनचर्या ठहर गई है। किसी की नौकरी दांव पर है, कहीं किसी का इलाज अधर में है, और कई परिवारों के लिए अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में शामिल होना भी असंभव हो गया है। प्रांत के 36 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद होने से स्थिति और कठिन हो गई है। न केवल व्यापार ठप है, बल्कि छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीकंसल्टेशन से इलाज कराने वाले मरीजों की सलाह, और रोजमर्रा की जानकारी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो चुका है। ऐसे माहौल में महंगी हवाई यात्रा ही एकमात्र बचा विकल्प है। लेकिन सीमित उड़ानों और भारी मांग के कारण टिकट की कीमतें जिस स्तर तक पहुंच गई हैं, वह लोगों की सामर्थ्य से बहुत ऊपर है।

सामान्य दिनों में 20 से 25 हजार में मिलने वाले टिकट अब 70 से 80 हजार में बिक रहे हैं, और तत्काल टिकट की कीमत एक लाख रुपये तक पहुंच गई है। यह स्थिति एक बड़े आर्थिक और मानवीय संकट का संकेत देती है। इस्लामाबाद के निवासी फहीम अल हसन बताते हैं कि क्वेटा में एक रिश्तेदार के निधन पर पूरा परिवार जाना चाहता था, लेकिन टिकट की कीमतों ने उन्हें रोक दिया। बसें और ट्रेनें बंद होने के कारण कोई वैकल्पिक साधन भी नहीं बचा। इसी तरह क्वेटा के सादुल्लाह कहते हैं कि घर में एक शादी थी, पर पूरा परिवार असहाय महसूस कर रहा है; क्योंकि इतने महंगे टिकट खरीदना परिवार की आर्थिक क्षमता से बाहर है। वे कहते हैं कि बलोचिस्तान से बाहर निकलना आज मानो एक "कैद की दीवार" फांदने जैसा हो गया है। हवाई किरायों में इस भारी बढ़ोतरी के खिलाफ बलोचिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अख्तर काकर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि एयरलाइंस बलोचिस्तान को लगातार नजरअंदाज कर रही हैं। फ्लाई जिन्ना, पीआईए और सेरेन एयर जैसी कंपनियां बड़े शहरों के लिए पर्याप्त उड़ानें संचालित करती हैं, लेकिन क्वेटा जैसे महत्वपूर्ण शहर के लिए उड़ानें बेहद सीमित रखी जाती हैं। मांग और उपलब्धता के इस असंतुलन ने टिकटों के दामों में अप्राकृतिक वृद्धि की है। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीआईए के सीईओ और नागरिक उड्डयन अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, और पूछा है कि उड़ानों की संख्या कम और किराया इतना अधिक क्यों रखा गया है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि बलोचिस्तान आज देश का वह प्रांत बन गया है, जिसे बार-बार अनदेखा किया जा रहा है।